नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
बजट अनुमान 2026–2027 पर
महापौर का अभिभाषण

मेरे हौसले की यही कहानी है,
जो कहा वो किया, आज आपको सुनानी है।
छूने को आसमां, अभी मैंने पंख खोले ही है,
शहर की दुआएं, साथ मेरे बुजुर्गों की मेहरबानी है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

रायपुर शहर, अपने गौरवशाली यशगाथा को स्वयं में समेटे हुए अन्य शहरों के लिए एक अग्रगामी मार्गदर्शक की भूमिका में शुरू से प्रतिष्ठित रहा है। रायपुर के प्रगतिशील सोच के साथ यहां उपलब्ध प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी इस शहर के नीति निर्धारण व नीति नियंताओं की सोच में शामिल रखना हर काल एवं परिस्थिति में अपरिहार्य रहा है।

बुझे हुए लौ को, फिर से हमें जलाना है,
अंधियारों से लड़ते–लड़ते, सूरज तक जाना है।।

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की माटी की महक और यहां निवासरत लाखों परिवारों की भावना से अभिभूत होकर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की नींव रखी। एक **"मिनी इंडिया"** के तौर पर विभिन्न संस्कृति, समाजों, विचारों का संगम बनकर राजधानी रायपुर ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, उसे दिशा देने व विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी मुझे रायपुर की जनता ने दी है, उसके लिए छत्तीसगढ़ की माटी में निवासरत समस्त नागरिकों को नमन करते हुए आज वर्तमान परिषद् के द्वितीय बजट सत्र में सम्मिलित सभी पार्षदों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ।

प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी सरकार ने देश के हर नागरिक के जीवन स्तर को खुशहाल, समृद्ध व गरिमामय बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएं हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग के जीवन में बदलाव आए और देश–प्रदेश, गांव, शहर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली व आत्मसम्मान का भाव जागृत हो, इसके अनुरूप निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मोदी जी के विकसित भारत के संकल्पों के बड़े विज़न को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य, उसके शहर और गांव विशेष रूचि ले रहे हैं।

रायपुर की महापौर होने के नाते मुझे यह बताने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन एवं उप–मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन विकास विभाग के भार साधक मंत्री आदरणीय श्री अरूण साव जी के कुशल निर्देशन में नगर पालिक निगम, रायपुर ने हमारे शहर के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया हैं, जो हमने नागरिकों द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तौर पर अपनी प्राथमिकताओं एवं इस परिषद् के प्रथम बजट की घोषणाओं में शामिल किया था।

मैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, उप–मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरूण साव जी, रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, रायपुर लोकसभा सांसद आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायकगण आदरणीय श्री राजेश मूणत जी, आदरणीय श्री सुनील सोनी जी, आदरणीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय श्री मोतीलाल साहू जी, आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी, नगर निगम रायपुर के सभापति आदरणीय श्री सूर्यकांत राठौड़ जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री आकाश तिवारी जी, सभी सम्मानित एम.आई.सी. सदस्यों, सभी सम्मानित जोन अध्यक्षों एवं साथी सम्मानित पार्षदगणों सहित आयुक्त श्री विश्वदीप जी के साथ निरंतर सेवा देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उनके सतत् सहयोग, परिश्रम व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं अपने शहर के प्रबुद्ध एवं वरिष्ठ नागरिकों, मीडिया साथियों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो रायपुर को बेहतर दिशा देने में अपना मार्गदर्शन देते हैं और हर सकरात्मक पहल पर हमारी परिषद का उत्साह वर्धन करते हैं।

आदरणीय सभापति जी,

अब शहर खामोश है, हवाएं भी धीमें चल रही है,
जिनके होने से कभी रौनक थी, उनकी कमी खल रही है।।

रायपुर शहर की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डालने के पूर्व मैं उन विभूतियों का स्मरण और नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने परिश्रम व बौद्धिकता से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के मान–सम्मान, गौरवगाथा को विश्व मंच पर आलोकित किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित **श्रद्धेय विनोद कुमार जी शुक्ल,** ख्यातिप्राप्त कवि **श्रद्धेय सुरेन्द्र दुबे जी** व रायपुर की प्रथम महिला विधायक रहीं **रजनी ताई उपासने जी** को हमनें इस वर्ष खोया है। नगर पालिक निगम परिवार की ओर से मैं इन विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।

सभापति महोदय,

रायपुर के मेरे प्रिय नागरिकों ने जब मुझे महापौर के रूप में निर्वाचित कर अपना आशीर्वाद दिया, तब इस शहर की बदहाली और नगर निगम के पैसों की बर्बादी वो सबसे बड़ी चुनौती रही, जो विरासत में पूर्ववर्ती महापौर और उनकी परिषद् ने मुझे सौंपा था। उस दौर में शहरी अधोसंरचना, शहरी स्वच्छता, पेयजल, निर्बाध यातायात प्रबंधन, तालाबों की खुशहाली, शहर की हरियाली, शहर की सफाई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ योजनाओं की पहुंच आम लोगों से दूर हो चुकी थी।

रायपुर की बेटी होने के नाते मुझे यह कहने में भी पीड़ा हो रही है कि तत्कालीन परिषद् ने स्मार्ट सिटी मिशन से 910 करोड़ रुपए, अमृत मिशन से 447 करोड़ रुपए, 24X7 जलापूर्ति योजना से 131 करोड़ रु. की बड़ी धनराशि प्राप्त होने के बाद भी बेपटरी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने में कोई रूचि और इच्छाशक्ति न दिखाकर केवल शहर को झूठे सजावट का मॉडल बनाकर रख दिया। नागरिक परेशान थे, लेकिन सुनवाई के लिए पूर्ववर्ती परिषद् पूरी तरह गैर जिम्मेदार रहीं।

उस जमाने की याद आई,
तो ज़ख्म कुछ पुराने निकले।
शहर में करना था जिसे सांप कांटे का इलाज,
उसके तहखाने से तो सांपों के ठिकाने निकले।।

जल भराव से जूझते मोहल्ले, पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार, चारों तरफ हो रहे अवैध अतिक्रमण तक की सुध लेने वाला कोई नहीं था, उल्टे बूढ़ातालाब परिसर में खर्च हुए करोड़ों रुपए, चौंक–चौराहों की सजावट पर बंदरबांट, बिना देख–रेख के टूटे–फूटे गौरवपथ, अधिकांश तालाबों, उद्यानों, सड़कों की दुर्गति, बेतरतीब बसाहट, अमृत मिशन जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की बदहाली, ग्रीन बेल्ट की गायब हरियाली जैसे कई कृत्य पूर्ववर्ती परिषद के कुशासन का जीता–जागता सबूत है, जिसे जनता आज भी जी भर कर कोसती है। पूर्व के कार्यकाल में तैयार की गई दोषपूर्ण नीतियां रायपुर नगर निगम के इतिहास का वो काला अध्याय है, जिसे सुशासन की राह पर तेजी से आगे बढ़ने वाला कोई भी शहर, सरकार या परिषद् कभी दोहराना नहीं चाहेगा।

जीवन की ढलती शाम नहीं, यह संघर्षों का विराम नहीं,
जो झुक जाए वह इंसान नहीं, जो रुक जाए वह तूफान नहीं।

सभापति महोदय,

चुनौतियों को पार करना हमनें **भारत रत्न अटल जी** से सीखा है। सुशासन का सीधा अर्थ शासन में जनता की आवाज़ को शामिल करना है। जनता की जरूरत के अनुरूप नीति का निर्धारण, योजना एवं कार्यक्रमों की जनता तक पहुंच सुनिश्चित कर उनके जीवन को सुखद, समृद्ध व खुशहाल बनाना ही हमारी प्राथमिकता में हमने पहले दिन से शामिल किया है।

योजना एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में हमने पूर्ववर्ती परिषद् की तरह कोई भी ऐसा शॉर्ट–कट नहीं अपनाया है, जिसमें पहले की तरह जनता की मेहनत व खून–पसीने की कमाई से मिले टैक्स के पैसों का अपव्यय हो, करोड़ों खर्च होने के बाद विकास गतिविधियों का नामों निशान न रहें और जनता अभावों के बीच जीवन यापन को मजबूर हो।

वर्तमान परिषद् के बजट निर्धारण में हमने दोहरी चुनौतियों का सामना किया है। जहां एक ओर हमने पूर्ववर्ती सरकार के गफ़लत और दोषपूर्ण नीतियों को सुधारने में अपनी ऊर्जा लगाई, वहीं दूसरी ओर जन आकांक्षाओं के अनुरूप दीर्घकालिक अधोसंरचना तैयार कर हर वर्ग की खुशहाली के लिए योजना के निर्धारण और क्रियान्वयन में अपनी शक्ति प्रदर्शित की है।

माननीय सभापति जी,

वर्तमान बजट प्रस्ताव एवं प्रावधानों पर चर्चा से पूर्व मैं बिन्दुवार अपने वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए रायपुर की जनता को अवगत कराना चाहूंगी कि हमने अपने हर घोषणा की माइक्रो मॉनिटरिंग की एवं इनमें नागरिक अपेक्षाओं के अनुरूप अपेक्षित प्रगति करते हुए अधिकांश को पूरा भी कर लिया है।

निश्चित आय के स्त्रोत के बीच बड़ी योजनाओं को पूर्णता की ओर ले जाने की दिशा में अपेक्षित प्रगति तभी संभव है, जब केन्द्र, राज्य शासन के साथ–साथ जन मानस का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता

है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की राज्य सरकार और रायपुर की वर्तमान परिषद् के ट्रिपल इंजन सरकार को स्थानीय नागरिकों का भरपूर स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से ही हम अपने योजनाओं एवं कार्यक्रमों को व्यापक गतिशीलता देकर जनसेवा के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के सहयोग से अपने इस पंचवर्षीय कार्यकाल में रायपुर को बृहद परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे–

1. रायपुर सहित अंचल के युवाओं को पठन–पाठन के लिए समुचित एवं हाईटेक सुविधा उपलब्ध कराने 500 सीटर के 02 **सेंट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण** का उल्लेख बजट अभिभाषण में किया गया था। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि नगर निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत दलदल सिवनी में 500 सीटर सेन्ट्रल लाइब्रेरी निर्माण हेतु 25 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से भूमि पूजन उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त साइंस कॉलेज रायपुर के समीप 22 करोड़ 79 लाख रु. की लागत से एक हजार सीटर लाइब्रेरी निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसका भूमि पूजन 23 जनवरी 2026 को माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी द्वारा किया गया है।

2. पूर्ववर्ती शहरी सरकार ने शहरी आवागमन के सुधार करने की बजाय अतिक्रमण को बढ़ावा देने में ज्यादा रूचि दिखाई, यही वजह है कि पिछले 02 कार्यकाल में स्मार्ट सिटी मिशन के 200 करोड़ रुपए, शहरी यातायात प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली प्रोजेक्ट में पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदतर होती रही। इसी तरह से शहर के चौक–चौराहों के विकास के लिए न तो कोई तकनीकी मापदंड निर्धारित किए गए, न ही आवागमन को व्यवस्थित करने की दिशा में कोई सोच अनुरूप कार्य किया गया। **मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना** के अंतर्गत हमारी वर्तमान परिषद् ने शहर के **18 प्रमुख चौक–चौराहों** के समग्र सुधार का

जो निर्णय प्रथम बजट में शामिल किया था, उसे पूरा करने के लिए हमने कार्य भी शुरू कर दिया है।

तेलीबांधा चौक के समीप **टेक्नों टॉवर** का उल्लेख गत बजट अभिभाषण में किया गया था। वर्तमान परिषद् ने प्रथम बजट की अपनी घोषणा के अनुरूप इस परियोजना को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री जी की पहल पर परियोजना को त्वरित प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। नगर निगम द्वारा विधिवत निविदा प्रक्रिया उपरांत कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस तरह टेक्नों टॉवर की सौगात अब रायपुर को शीघ्र मिलेगी। याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले दोनों महापौर टेक्नों टॉवर निर्माण की चर्चा बस अपने बजट अभिभाषण में लगातार करते रहे, किन्तु दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में इस दिशा में वें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते थे।

3. राजधानी रायपुर के समग्र व संतुलित विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी राशि की कमी नहीं होने दे रहें हैं। पूर्व का कार्यकाल चौक–चौराहों को सजाने, उद्यानों में सौंदर्यीकरण पर किये गए फालतू खर्च के नाम रहा। आज पूरा शहर, घूम–घूमकर इनके कार्यकाल में किए गए करोड़ों के खर्चे से हुए कथित विकास कार्यों की निशानी ढूंढ रहा है, जो उनके झूठे सपनों व वादों की तरह मिट्टी में मिल चुका है।

हमारी परिषद् ने पूर्व के कार्यकाल से बहुत कुछ सीखा है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इनके कार्यकाल का गंभीरता पूर्वक अध्ययन व मनन करना चाहिए और विस्तार से समझना चाहिए कि जन भावना का सम्मान न करना, जनहित की अनदेखी करना, झूठ के नींव व दूसरे के सहारे पर खड़ी ऐसी इमारत जब जमींदोज़ होती है, तो पीढ़ियां ऐसे नवाबों को नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ने लायक तक नहीं समझती है।

वर्तमान परिषद् ने पहले जनता की आवाज को सुना, उनकी जरूरतों को समझा, अपनी प्राथमिकताएं तय की और बजट अभिभाषण में अपने संकल्प के तौर पर शामिल कर अपने नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाई। नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुड़ी अपनी घोषणाओं को पूरा करने की संकल्प शक्ति हमनें दिखाई है।

अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत 37 करोड़ 61 लाख रु. के विभिन्न विकास कार्य गत् बजट अभिभाषण में शामिल किए गए थे, जिसमें 15 करोड़ रुपए की लागत से गौरव पथ चौड़ीकरण कार्य, सी. एस.ई.बी. चौक से पचपेड़ी नाका तक सड़क निर्माण कार्य हेतु भी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से 08 अक्टूबर 2025 को मिली स्वीकृति उपरांत निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर रायपुर नगर निगम द्वारा दर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

4. महिला स्वावलंबन, सशक्तिकरण व आत्मनिर्भरता हेतु **दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** के अंतर्गत शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने 1530 स्व–सहायता समूहों को **बैंक लिंकेज से जोड़कर** 26 करोड़ 30 लाख रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। साथ ही वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण भी शहरी महिलाओं को प्रदान किया गया है।

5. **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के साथ ही साथ डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण देने की योजना गत वित्तीय वर्ष में तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण प्रदान कर **डिजिटली एक्टिव** किया गया और उन्हें शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।

6. पूर्व के अभिभाषण में हमनें **मार्केट डेव्हलपमेंट प्लान** के तहत वेंडिंग जोन विकसित करने की चर्चा की थी, किन्तु किसी भी स्थल पर वेंडिंग जोन

के लिये स्थान चयन की प्रक्रिया के दौरान अधिकांश स्थलों पर विवाद की स्थिति सामने आती है। नगर निवेश, यातायात व पुलिस की टीम के संयुक्त निरीक्षण के बाद भी स्थिति विवादित ही रहती है, ऐसे में वेंडिंग जोन के चिन्हांकन में विलंब स्वाभाविक है। आज के सामान्य सभा के एजेण्डे में वेंडिंग जोन का विषय भी लेकर आये हैं आप सभी पार्षदों से अनुरोध है कि चर्चा के दौरान अपने क्षेत्र में वेडिंग जोन के निर्धारण हेतु स्थल चिन्हित करने के लिये अपना सुझाव अवश्य दें।

7. समाज के हर वर्ग तक सुविधाओं की पहुंच निर्धारित हो सके, शहर के युवा, महिलाएं, बुजुर्गों के साथ–साथ **तृतीय लिंग समुदाय** को भी समानता के अधिकारों के तहत आवश्यक बुनियादी सुविधाएं व जीवन को दिशा देने के अवसर प्राप्त हो इसके लिए नगर निगम नियमित तौर पर तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों से विमर्श करता है और उनके परामर्श के अनुरूप योजना, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, प्रशिक्षण की सुविधा व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में जुटा हुआ है।

8. रायपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की आवासीय समस्या को दूर करने रायपुर में कामकाजी **महिला वसति गृह** निर्माण की घोषणा गत् वित्तीय बजट के अभिभाषण में की गई थी। पूर्ववर्ती महापौर ने अपने कार्यकाल में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए वूमेन्स वर्किंग हॉस्टल के बड़े वायदे किए थे, किन्तु यह जानकर भी अफसोस होता है कि 2015 से 2024 तक के कार्यकाल में रायपुर आकर काम करने वाली हमारी बहनों को सिर्फ झूठी दिलासा मिली और यहां तक कि फुंडहर में तैयार इमारत तक को भी कामकाजी महिलाओं को देने के बजाय योग आयोग को सौपनें की बात शुरू हो गयी। हालत यह रही कि न वहां योग आयोग की गतिविधियां शुरू हुई और न ही हमारी बहनों को आवास के लिए स्थान ही मिल पाया लेकिन अब हमारी वर्तमान परिषद् की पहल पर

रायपुर के 02 स्थानों पंडरी और नरैया तालाब के समीप वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

9. सार्वजनिक स्थलों विशेषकर बाजारों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में महिला प्रसाधन संबंधित परेशानियों को दूर करने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत **सेनेटरी वेंडिंग मशीन** की स्थापना हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है।

10. सार्वजनिक स्थलों विशेषकर **प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बीएसयूपी** के तहत मठपुरैना एवं भाठागांव में निर्मित आवासीय परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसके तहत 140 लाख रु. की लागत से 268 कैमरे स्थापित किए गए है। इन कैमरों का संचालन मुजगहन थाना एवं पुरानी बस्ती थाना द्वारा किया जा रहा है।

11. नागरिक सेवाओं के संबंध में नगर निगम मुख्यालय अथवा जोन कार्यालय में आने वाली महिला आगंतुकों व कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए **महिला प्रसाधन केन्द्र में सेनेटरी नेपकीन वेंडिंग मशीन व इंसीनेटर** लगाए जाने की घोषणा गत् बजट अभिभाषण में की गई थी। इस हेतु तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

12. एक महिला होने के नाते रायपुर की उन हजारों महिलाओं की आर्थिक मनोदशा, अभावों की वेदना और आगे बढ़ने की अद्भुत इच्छा शक्ति से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। निम्न व मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़कर उनकी रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकताओं में शुरू से शामिल रहा है। मोवा में निर्मित जिस **लेडिस गारमेंट फैक्ट्री** शेड के संचालन हेतु हमनें अपने शहर की बहनों के आर्थिक हितों के संरक्षण को वरीयता देते हुए अभिव्यक्ति की अभिरूचि के मापदण्डों की पुनः समीक्षा की है। पूर्व में बड़े व्यवासायिक प्रतिष्ठानों

को इसके संचालन का दायित्व देने और महिलाओं को उनसे जोड़कर गतिविधियों को आगे बढ़ाने की योजना थी किन्तु अब हम महिला समूहों को प्रमुखता के साथ इसके संचालन में आगे लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

13. युवाओं को अध्ययन की सुविधाएं रायपुर में इस तरह से मिले कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए किसी महानगर में जाकर भटकना न पड़े इस दिशा में हमने नालंदा परिसर की तर्ज पर हाईटेक लाइब्रेरी की शुरूआत की है। लाइब्रेरी निर्माण के अगले चरण में युवाओं को **यूथ हॉस्टल** की सुविधाएं भी उपलब्ध हो, इस दिशा में हम अपनी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे रहे है।

14. तेजी से बढ़ते जनसंख्या घनत्व की वजह से हमारे शहर के बच्चे खेलकूद जैसी सामान्य गतिविधियों से दूर हो रहे थे, मोबाइल व ऑनलाइन गेमिंग से हर पालक चिंतित हो रहा था, हमने इस दुविधा को समझा है। बच्चे व युवा खेल गतिविधियों से जुड़कर सामाजिक सद्भाव के साथ आगे बढ़े इस दिशा में हमने काम किया है और विभिन्न जोन के **07 स्थलों पर बाक्स क्रिकेट** तैयार किया है।

15. रायपुर के ऐतिहासिक, पौराणिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित महादेव घाट के जीर्णोद्धार के लिए पूर्ववर्ती दोनों महापौर ने बड़ी घोषणाएं की, किन्तु इन घोषणाओं के क्रियान्वयन में शहर को इनकी कोई इच्छा शक्ति देखने नहीं मिली। नतीजा यह रहा कि 15 सालों में महादेव घाट और रायपुर शहर की लाइफ लाइन खारून नदी अव्यवस्थाओं से पटी रही, किंतु अब लोक निर्माण विभाग द्वारा **खारून रिवर फ्रंट** परियोजना के तहत इसका समग्र विकास किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।

16. **इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्रिस्टल ऑर्केड, कमर्शियल हब और ट्रेड टॉवर** जैसे महत्वपूर्ण हब तैयार कर व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से बिजनेस सेंटर तैयार करने की हमने जो घोषणा की थी। उसके लिए शंकर नगर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और डुमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट निर्माण हेतु 100 करोड़ रु. के **म्युनिसिपल बांड** जारी किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से की गई थी। इसके परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब इन कार्यों को म्युनिसिपल बांड जारी कर उससे प्राप्त होने वाली राशि से कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।

17. **दिव्यांग पार्क** हमारे शहर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस वित्तीय वर्ष में हमारे प्रस्ताव पर दिव्यांग पार्क विकसित करने हेतु **सिपडा योजना** अंतर्गत लगभग राशि रु. 10 करोड़ की स्वीकृति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से विगत 09 अक्टूबर 2025 को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

18. पहले लघु उद्यमी व पथ विक्रेता अपनी रोजी–रोटी व उचित स्थान पर व्यवसाय हेतु चिंतित रहते थे और आवागमन अवरोध होने व नियम विरूद्ध गुमटी ठेला लगाने के कारण जब्ती जैसी अप्रिय स्थितियों का सामना करते हुए इनका पूरा परिवार मानसिक प्रताड़नाओं का शिकार होता रहा है। लघु उद्यमियों व पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा, उचित जीवन स्तर व उपयुक्त स्थल मुहैया कराकर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में सहयोग देना भी हमने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसके लिए नगर निगम द्वारा सभी की सहमति से **वेंडिंग जोन** के लिये स्थल चयन कर इसे चौपाटी के स्वरूप में विकसित किया जायेगा।

19. युवाओं को **स्टार्ट–अप और इनोवेशन सेंटर** से जोड़कर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम का लाभ दिलाने की घोषणा पूर्ववर्ती मेयर द्वारा की गई थी,

इसके लिए ISBT भाठागांव, जयस्तंभ चौक और कलेक्टोरेट मल्टीलेवल पार्किंग में नगर निगम द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर इन परिसरों में विस्तृत स्थल उपलब्ध कराया गया था। इनके संचालन के कड़वे अनुभव से सीख लेते हुए यहां उपलब्ध सुविधाओं से युवाओं को हो रहे लाभ और नगर निगम को होने वाली आय का विस्तार से परीक्षण उपरांत इसके भावी संचालन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

20. **तालाबों के संरक्षण, संवर्धन** की बात जब भी सामने आती है, तो पूर्ववर्ती परिषद् के दोषपूर्ण नीतियों, क्रियान्वयन की अशुद्धियों, आकंठ भ्रष्टाचार से कराहते तालाबों की वेदना से हर रायपुरवासी की तरह मेरा भी मन द्रवित होता है। **15वें वित्त आयोग** के जल घटक में 74 करोड़ रु. की राशि तालाबों के संरक्षण व संवर्धन में व्यय की जानी चाहिए थी, किन्तु पूर्ववर्ती परिषद् ने उस 74 करोड़ रु. में से मात्र 5 करोड़ रु. केवल पहाड़ी और बघवा तालाब में ही खर्च किए गए और शेष 69 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि भारी–भरकम परियोजना अमृत मिशन, जिसमें पहले से ही 450 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत थी, उस पर ही खर्च कर दिए गए। यही वजह है कि शहर के तालाब दम तोड़ते रहें और केन्द्र सरकार द्वारा रायपुर के तालाबों को जीवन देने भेजी गई राशि दूसरी परियोजना में लगा दी गई।

इनकी इन्हीं नाकामियों से सबक लेकर हमारी परिषद् ने छुईया तालाब जैसे अन्य तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए योजना निर्धारण को गंभीरता से लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत भी कार्य स्थल विवादित होने के कारण छुईया तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य आरंभ होने में विलंब हो रहा है, इसके लिए निगम अधिकारियों से कहा गया है कि निर्माण से पहले विवाद दूर करें एवं संपूर्ण समाधान और विचार–विमर्श के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लें। इसके अलावा करबला तालाब, जोरा तालाब में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से विचार विमर्श उपरांत

अब शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप इन तालाबों का संरक्षण व संवर्धन किया जाएगा।

21. पार्किंग सुविधा किसी भी शहर के लिए आवश्यक है एवं सीमित भू–खंड उपलब्धता की वजह से रायपुर जैसे शहर के लिए यह स्थिति बड़ी परेशानी खड़ी करती है। नगर निगम मुख्यालय व पंडरी में **स्वचालित पार्किंग** का निर्माण प्रगति पर है।

22. मुख्य मार्गों व सड़कों पर लगने वाले बाजारों से आवागमन प्रभावित न हो और इन **बाजारों के सुव्यवस्थित संचालन** सुनिश्चित हो, इसके लिए नगर निवेश की सेन्ट्रल टीम व जोन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निगम प्रशासन द्वारा संडे बाजार, मौदहापारा मार्ग, एम.जी. रोड सहित मुख्य व आंतरिक मार्गों पर लगने वाले बाजारों को व्यवस्थित किए जाने का अभियान शुरू किया गया है, जो निरंतर आगे भी जारी रहेगा।

23. **शुद्ध पेयजल की उपलब्धता** किसी भी नगरीय निकाय के निर्वाचित परिषद् की मूलभूत जवाबदारी होती है। जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार की जरूरत भी समय–समय पर महसूस की जाती है।

पूर्ववर्ती परिषद् ने अभी तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की दिशा में व्यवस्थाओं के विस्तार को पूरी तरह से नज़र अंदाज किया। अमृत मिशन से 14 बड़े जलागार बनाए गए, पर इनसे बस्तियों को जोड़ने पाइप–लाइन की व्यवस्था का न होना यह दर्शाता है कि पूर्ववर्ती महापौर शहर को पेयजल की समुचित सुविधा देने की ठोस रणनीति पर काम करने में असफल रहें और विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में इस शहर को टैंकर के भरोसे रखकर आम लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसने को मजबूर रखा। अमृत मिशन से राशि 447 करोड़ रुपए, 24X7 जलापूर्ति योजना हेतु 130 करोड़ 67 लाख रु. जैसी महत्वपूर्ण योजना का

क्रियान्वयन यदि उचित ढंग से किया जाता, तो रायपुरवासियों को पेयजल की बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ता। अमृत मिशन से 14 बड़ी टंकिया तो बनाई गई, किन्तु इन्हें पाइप लाइन से जोड़ने की व्यवस्था नहीं रखी गई। हमारी परिषद् ने पेयजल समस्या को दूर करने के लिए तकनीकी परीक्षण उपरांत इनमें से कुछ पानी टंकियों को पाइपलाइन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है।

रायपुर शहर के किसी भी क्षेत्र में पेयजल या अन्य कोई समस्या का बने रहना पीड़ा जनक है। जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि स्थानीय शासन में परिषदें और उनका कार्यकाल आती–जाती रहेंगी, लेकिन इस शहर के विकास के लिए यह जरूरी है कि अपने कार्यकाल में अपनी योग्यता का शत्–प्रतिशत् शहर के विकास में समर्पित करें, जिससे कि हर कार्यकाल की छोटी–बड़ी उपलब्धियों से शहर के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में निरंतर प्रगति हो और उपलब्धियों के साथ हमारा शहर विकसित शहरों जैसी सुविधाओं से जुड़ता चले। सभी जनप्रतिनिधि स्वयं भी इस शहर के विकास में अपनी भागीदारी दे पाने के गौरव से सर ऊंचा कर चल सकें, इस दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा। रायपुर की जनता पूर्ववर्ती महापौर और उनकी परिषद् को प्रतिदिन उनके कार्यकाल की इस विफलता का दोष देती है, तो उन्हें भी इस सच्चाई को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि सुविधाओं के विस्तार की जिम्मेदारी निभाने में उनसे बड़ी चूक हुई है।

हमारी वर्तमान परिषद् ने पेयजल समस्या को दूर करने एवं नगर निगम के जल अमले को प्रशासनिक और तकनीकी दक्षता देने 16 जनवरी 2026 को **जल बोर्ड का गठन** किया है। जल बोर्ड के माध्यम से पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था व सार्वजनिक जल आपूर्ति की सेंट्रल मॉनिटरिंग शुरू हुई है। पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आई तकनीकी खामियों की पहचान में समय लगता था, किन्तु केन्द्रीकृत व्यवस्था जल बोर्ड के माध्यम से हो जाने से खामियों की पहचान आसान हो रही है। इसके लिए जल बोर्ड के माध्यम से पूरे शहर में जल आपूर्ति हेतु बिछाए

गए पाइप लाइन का मैप तैयार किया जा रहा है। यह बोर्ड इंटेकवेल से लेकर वितरण पाइप लाइन के अंतिम छोर तक का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा है। शहर के जल नेटवर्क में पारदर्शिता लाने हेतु पाइप लाइन का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में 70 प्रतिशत नेटवर्क का डाटा डिजिटल हो चुका है। इस प्रक्रिया से जहां पुरानी पाइप लाइनों का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, वहीं लो–प्रेशर की समस्या का सटीक समाधान त्वरित गति से संभव हो सकेगा। जल बोर्ड के माध्यम से पानी का अपव्यय रोकने में भी मदद मिलेगी।

जल बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है और हाल ही में जोन क्र.–1 सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनावश्यक सार्वजनिक नलों को बंद करने जैसे बड़े कदम भी उनके द्वारा उठाए गए हैं। जल बोर्ड विभिन्न जोनों के मध्य समन्वय स्थापित कर तकनीकी बाधाओं को दूर करने में भी सक्षम है। हाल ही में अशोका रतन, कुशालपुर सहित अन्य कई क्षेत्रों में आ रही जलापूर्ति की व्यवहारिक दिक्कतों को जल बोर्ड ने सुगमता पूर्वक दूर किया है।

जल बोर्ड के गठन से वर्तमान चुनौतियों के साथ ही साथ जलापूर्ति व्यवस्था की भावी चुनौतियों की पहचान एवं उसका निवारण सरल होगा। **जल बोर्ड** का यह भी दायित्व होगा कि शहर के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में पेजयल की उपलब्धता हो, इसके लिए सार्वजनिक जल आपूर्ति का सुदृढ़ नेटवर्क तैयार करें। जल की गुणवत्ता, उपलब्धता व इसकी मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए जल संचयन, संरक्षण, संवर्धन की प्रणाली तैयार करें। जल बोर्ड का कार्य व्यापक पैमाने पर पूरे शहर की व्यवस्थाओं से संबंधित है, इसलिए इस वर्ष इसकी सुविधाओं का लाभ तत्काल दिखाई नहीं देगा, लेकिन डिजिटलीकरण का कार्य शत्–प्रतिशत् पूर्ण होने के बाद आने वाले वर्षों में तकनीकों के बेहतर समन्वय के साथ जल बोर्ड का महत्व स्पष्ट दिखाई देगा।

एक ओर जहां हमने होटल, रेस्टोरेंट में **"शुद्ध पेयजल–मेरा अधिकार"** के आधार पर निःशुल्क पेयजल प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है, साथ

ही अपनी सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली को भी अपग्रेड करने की दिशा में काम शुरू किया है। इस समय 310 एम.एल.डी. क्षमता के फिल्टर प्लांट के माध्यम से 45 जलागारों में जल आपूर्ति की जाती है।

शहर के पुराने कुओं के संरक्षण की दिशा में हमने अपनी कार्यवाही शुरू की है, **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भारत सरकार** की विशेष टीम ने शहर के पुराने बसाहट वाले क्षेत्रों विशेषकर ब्राम्हणपारा, पुरानी बस्ती, लाखे नगर, आमापारा सहित रिहायशी क्षेत्रों के पुराने कुओं के पुनर्जीवन हेतु गहन सर्वेक्षण शुरू किया है एवं हमारा यह प्रयास रहेगा, कि इन कुओं को नया जीवन देकर जल संरक्षण व संवर्धन से आम नागरिकों को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ें। इसके अलावा हमने इस वर्ष **गोगांव और पुरानी बस्ती क्षेत्र के पुराने कुओं** के संरक्षण का कार्य भी पूरा किया है। नगर निगम द्वारा एक करोड़ की लागत से 65 नवीन बोर खनन भी कराए गए, जिससे कि पेयजल से जुड़ी समस्या का निदान हो सकें।

24. अमृत मिशन योजना में छूटे हुए टंकियों के कमांड एरिया में प्रस्तावित कार्यों को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जा रहा है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व है कि इस वर्ष हमने चंदनीडीह एकता कॉलोनी, सोनडोंगरी, संकल्प वाटिका, विधायक कॉलोनी, टेकारी मार्ग व देवपुरी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में पाइप लाइन पहुंचाकर वहां कि वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को काफी हद तक दूर करने में सफलता पाई है। एकता कॉलोनी जहां, पेयजल समस्या के कारण प्रतिदिन लगभग 25 टैंकर की मांग बनीं रहती थी, वहां एक भी टैंकर की जरूरत न होना नगर निगम के लिए उत्साह जनक उपलब्धि है। अब हम ऐसे ही अन्य क्षेत्रों को भी **टैंकर फ्री** करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करेंगे।

25. चिंगरी नाला महादेव घाट के पास दूषित जल ओव्हर फ्लो होकर नदी में समाहित होता है, गत् वित्तीय वर्ष के बजट में हमनें इस पर आवश्यक

कार्यवाही करने की घोषणा की थी, इसी अनुक्रम में मैं अवगत कराना चाहूंगी कि राज्य शासन द्वारा दूषित जल के ओव्हर फ्लो के कारणों की जांच करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया एवं निरीक्षण उपरांत उक्त कमेटी की अनुशंसा पर वियर की ऊंचाई बढ़ाने एवं नाले की लाइनिंग कार्य हेतु **11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर** स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया गया है। स्वीकृति उपरांत इस दिशा में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित कर दूषित जल को नदी में समाहित होने से रोकने संबंधी प्रबंध किए जाएंगे।

26. निमोरा में 122 करोड़ 24 लाख रू. की लागत **60 एम.एल.डी. एस. टी.पी. निर्माण** हेतु शासन को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है।

27. लाभांडी एवं फुंडहर क्षेत्र में **राइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एवं घरेलू नल कनेक्शन** सुनिश्चित करने हेतु 41 करोड़ 92 लाख रू. लागत के इस कार्य हेतु शासन से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य प्रारंभ कर 24 माह के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

28. **ठक्कर बापा वार्ड** क्रमांक–17 में 2000 किलो लीटर क्षमता एवं 25 मीटर स्टेजिग के नये जलागार, जिसकी लागत 19 करोड़ 61 लाख रु. है। इस परिषद् के प्रथम बजट घोषणा के अनुरूप उच्च स्तरीय जलागार निर्माण का कार्य प्रगति पर है। **आईएसबीटी पानी टंकी** में तकनीकी समस्या आने के कारण इसे सड्डू क्षेत्र में निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे शासन से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

29. **अमृत मिशन योजना** अंतर्गत जल का अपव्यय रोकने व इसे पुनः उपयोग में लाने 185 एम.एल.डी. शोधित जल को उपचारित कर औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाने की जो योजना नगर निगम ने वर्तमान में तैयार की है, उसके तहत निमोरा, कारा एवं चंदनीडीह एस.टी.पी. से कुल 103

एम.एल.डी. उपचारित जल प्रदान किए जाने हेतु अबतक 06 फर्मों से नगर निगम ने एम.ओ.यू. साइन किया है।

30. नागरिक सुविधाओं व नगर पालिक सेवाओं का लाभ लेने में नागरिकों को कोई परेशानी न हो, उनके शिकायत व सुझाव पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए रायपुर नगर निगम ने प्रभावी संचार तंत्र विकसित करने का निर्णय लिया था। इस परिप्रेक्ष्य में मोर रायपुर ऐप, टोल फ्री सेवा निदान–1100 के साथ ही रायपुर नगर निगम का **चैट बॉट** संचालित है, जिससे जुड़कर कोई भी नागरिक नगर निगम सेवाओं व सुविधाओं का लाभ ले सकते है एवं अपनी शिकायत निराकरण हेतु दर्ज कर सकते है।

31. विभिन्न विभागों द्वारा शहर में तैयार की गई सुविधाओं की देखरेख भी नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी होती है। रायपुर के विभिन्न स्थलों पर वरिष्ठ नागरिकों के आमोद–प्रमोद, वार्तालाप एवं सामूहिक मेलजोल के लिए निर्मित **बापू की कुटिया** में से 09 कुटिया का समुचित संचालन व संधारण स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है, शेष अन्य बापू की कुटिया के संचालन व संधारण के लिए स्वयंसेवी संगठनों से विचार–विमर्श किया जा रहा है। सभी ओपन जिम का संचालन व संधारण नगर निगम द्वारा किया जाएगा।

32. नालंदा, तक्षशिला व सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा शहर में संचालित अन्य लाइब्रेरी के लिए **सुव्यवस्थित संचालन** हेतु जोन अधिकारियों से कहा गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे युवाओं को उचित वातावरण मिले इस हेतु इन स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं नगर निगम द्वारा सुलभ करायी जाती है।

33. वर्तमान परिषद् ने मुक्तिधामों के उन्नयन व बुनियादी सुविधाओं की ओर भी ध्यान देने की शुरूआत की है। रायपुर नगर निगम द्वारा महादेव घाट, मारवाड़ी श्मशान घाट एवं देवेन्द्र नगर मुक्तिधाम में 15 वें वित्त आयोग मद 97 लाख 52 हजार रुपए की लागत से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी स्थापना एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। कुल 17 मुक्तिधाम हेतु 11 करोड़ की राशि अनुमानित है, जिसमें वर्तमान मे 2 मुक्तिधाम की स्वीकृति वर्तमान में प्राप्त हो चुकी हैं।

34. यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हरित एवं पर्यावरणीय कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत गैप प्लांटेशन के तहत 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त रु. 80 लाख की राशि से वृहद वृक्षारोपण किया गया है जिसमे कुल 6,819 पेड़ लगाए गए। इसी प्रकार अर्बन पाकेट फारेस्ट योजना के अंतर्गत 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त रू. 98 लाख 86 हजार की राशि से मियावाकी पद्धति द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कुल 25,605 पौधे एवं पेड लगाए गए हैं। नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत इंटर स्टेट बस टर्मिनल के समक्ष एक नवीन उद्यान का निर्माण नवग्रह उद्यान के रूम मे किया जा रहा है, जो रायपुर की सुंदरता मे वृद्धि करने के साथ ही साथ एक आकर्षक, सुव्यवस्थित एवं थीम आधारित हरित स्थल के रूप मे विकसित होगा।

35. नगर निगम मुख्यालय में संस्थागत सुधार हेतु वित्तीय प्रबंधन और प्रोजेक्ट प्रबंधन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत ई–फाइलिंग व मॉनिटरिंग हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण की योजना है। इससे कार्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता में सुधार और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

36. रायपुर शहर के समग्र, संतुलित विकास के लिए रायपुर नगर निगम के अधीन सभी जोन के वार्ड में **सिटी डेव्हलपमेंट प्लान** तैयार कर लिया गया है, जिसके आधार पर विकास कार्यों, बाजारों का निर्धारण व्यवस्थित रूप से किए जाने की शुरूआत हो चुकी है।

37. शहर के 04 प्रमुख द्वारों पर म्यूरल साइनेज निर्माण की योजना के संबंध में निर्णय ले लिया गया है एवं कार्यादेश उपरांत शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

38. शहरी स्वच्छता व साफ–सफाई हर शहर की पहचान बनती है। रायपुर शहर को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश के स्वच्छ शहरों में चतुर्थ रैंक प्राप्त होना गर्व का विषय है। इसके लिए पूरी परिषद् सहित विशेषकर नगर निगम में कार्यरत सफाई मित्र, स्वच्छता दीदियां बधाई की पात्र हैं। रायपुर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया है एवं **माइक्रो मॉनिटरिंग** के जरिए शहर के हर वार्ड को जोड़ने की शुरूआत की है। निर्माण कार्यों से निकलने वाले अपशिष्ट और इससे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने सभी जोन के निर्माण क्षेत्र में ग्रीन नेट लगाने के निर्देश दिए गए है।

39. महानगर का स्वरूप प्राप्त कर चुके रायपुर शहर में नियमित साफ–सफाई एक बड़ी चुनौती है। महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ–साथ मुख्य व आंतरिक मार्गों की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सफाई मित्र व स्वच्छता दीदियां निरंतर श्रम करती है। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था में लगी टीम को निर्देशित किया गया है कि मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को यांत्रिक सफाई हेतु जोड़ें और यहां लगे मानव बल को आंतरिक मार्गों की सफाई व्यवस्था हेतु तैनात करें।

40. तालाबों में जलकुंभियां एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जाती है। गत् बजट घोषणा में तालाबों के संरक्षण, संवर्धन एवं सौंदर्यीकरण व जल कुंभियों के उन्मूलन हेतु मशीनों के उपयोग का निर्णय लिया था, इस अनुक्रम में 1 करोड़ 50 लाख रु. की लागत से **एक्वेटिक फीड हार्वेस्टर मशीन** क्रय किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा तालाबों के संरक्षण, संवर्धन व सौंदर्यीकरण हेतु शासन के निर्देशों के अनुरूप पीपीपी मॉडल कराए जाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

41. मच्छर से बचाव एवं एंटी लार्वा व दवाओं के नियमित छिड़काव के साथ नालियों को ढंकने की कार्य योजना पर निगम ने अमल शुरू किया है। इस हेतु 16 लाख 94 हजार रु. की लागत से नये फॉगिंग मशीन क्रय किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

42. उत्कृष्ट कार्य कर शहर को गौरवान्वित करने वाले **सफाई मित्रों व स्वच्छता दीदियों** को हमारी परिषद् ने **सम्मान व प्रोत्साहन राशि** से नवाज़ा है। इनके अलावा वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों महिला शक्ति को जोड़ने की दिशा में भी नगर निगम ने कार्य किया है और **वूमन फॉर ट्री** कार्यक्रम से जोड़कर स्व–सहायता समूह के बहनों के लिए मानदेय का निर्धारण किया गया है।

43. रायपुर जिला प्रशासन व अंतर्विभागीय समन्वय के साथ समय–समय पर हेल्थ कैम्प आयोजित किए गए है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों व निगम अधिकारियों–कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

44. नगर निगम मुख्यालय व जोन कार्यालयों में महिला अधिकारी, कर्मचारी एवं आगंतुक महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड मशीन व इंसीनेटर हेतु निविदा प्रकिया की जा रही है।

45. नगर निगम मुख्यालय में शासकीय कार्य व सुविधाओं के लिए निगम कार्यालय आने वाली माताओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए बेबी फीडिंग सेंटर को सुव्यवस्थित कर संचालन शुरू किया गया है।

46. **नगर निगम में कार्यरत स्वच्छता दीदियों** को यूनिफार्म देने के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है एवं उन्हें योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन में बड़े बदलाव की सोच के साथ स्वच्छता दीदियों को प्रेरित किया जा रहा है।

47. नगर निगम की सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने **मोर संगवारी एप्प** की सुविधा संचालित है। इसके माध्यम से घर बैठे जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त किए जा सकते है। इस वर्ष जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों से संबंधित 46,662 प्रकरणों में मोर संगवारी एप्प की सुविधा नागरिकों ने ली हैं।

48. स्वच्छ रायपुर की संकल्पना में नागरिक सहयोग आवश्यक है। स्थानीय युवाओं विभिन्न सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों के साथ ही आम नागरिकों को जोड़ने व **रायपुर को स्वच्छतम शहर के रूप में स्थापित करने** हेतु सभी से सहयोग की अपील की जा रही है। सभी सम्मानित पार्षदों से भी अनुरोध है कि स्वच्छता विषयक प्रबंधनों से अपने वार्ड वासियों को जोड़ने व सभी को प्रेरित करने सक्रिय व सकारात्मक पहल करेंगे।

49. बड़े व्यावसायिक व आवासीय **परिसरों में कम्पोस्टिंग मशीन** स्थापना के प्रयास नगर निगम द्वारा शुरू किए गए है। इसके अंतर्गत 03 बड़े

व्यावसायिक परिसरों पार्थिवी प्रोविंस, सरोना, वी.आई.पी. सिटी सड्डू, ऐश्वर्या वाइंड मिल में कम्पोस्टिंग मशीन की स्थापना कर इंस्टालेशन कार्य प्रगति पर है।

50. माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि **ट्रीटेड पानी के औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देने** के लिए निमोरा एसटीपी से तिल्दा स्थित एक औद्योगिक इकाई तक प्रतिदिन 68 लाख लीटर ट्रीटेड पानी सप्लाई की योजना तैयार की गई है। इस हेतु लगभग 48 किलो मीटर की पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिसका डीपीआर 800 करोड़ रु. की अनुमानित लागत अनुसार तैयार की गई है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम एपीआई इस्पात को प्रतिदिन 5 लाख लीटर शोधित जल बेच रहा है, जिससे निगम को प्रतिमाह 8 लाख 50 हजार रुपए की आय हो रही है। नये औद्योगिक अनुबंध के पश्चात यह आय बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपए प्रतिमाह तक हो जाएगी। इस तरह जहां एक ओर दूषित जल का पुनः उपयोग होगा, वहीं नगर निगम को राजस्व आय भी होगी।

51. **सी. एंड डी. प्लांट के सुचारू संचालन** के लिए सभी जोन को सी. एंड डी. को प्लांट से पहुंचाने निर्देशित किया जा रहा है। यहां निर्मित पेवर ब्लॉक, गमले आदि के उपयोग नगर निगम के निर्माण कार्यों में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सड़क किनारे फैले भवन विध्वंस सामग्री को प्लांट तक लाने की सुगम व्यवस्था निर्धारित करने, इसके व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

52. कचरे के उचित प्रबंधन हेतु ट्रांसफर स्टेशन एवं सेकेंडरी प्वॉइंट का चिन्हांकन कर 15वें वित्त आयोग अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ किया गया है।

53. प्रसाधन की समुचित व्यवस्था अंतर्गत 3 करोड़ 10 लाख रू. की लागत से 13 नग **आकांक्षी आधुनिक प्रसाधन गृह** निर्माण की कार्य योजना पर अमल शुरू किया गया है, जिनमें से 11 स्थानों पर आकांक्षी शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं शेष 02 स्थलों पर शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

54. **पुलिस कमिश्नर प्रणाली** लागू होने के पश्चात रायपुर नगर निगम ने यातायात प्रबंधन, सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस व सार्थक प्रबंध सुनिश्चित करने की प्रभावी कार्यवाही शुरू की है। टीम प्रहरी, जिसमें नगर निगम, यातायात पुलिस, जिला प्रशासन की टीम शामिल होती है। इस संयुक्त टीम ने मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने निरंतर कार्यवाही शुरू की है।

55. गीले कचरे से **कम्प्रेस्ड बायोगैस बनाए जाने की योजना** तैयार की गई है। इस हेतु नया रायपुर के ग्राम कुर्रू में स्थल चयन कर लिया है।

56. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और नगर निगम की ट्रिपल इंजन सरकार ने आम नागरिकों से सीधे तौर पर जुड़े सार्वजनिक परिवहन सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया है। बसों के संचालन में हम अपने शहर के पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए रायपुर शहर के नागरिको को सहज, सुलभ एवं आधुनिक यातायात सुविधा प्रदान करने केन्द्र शासन की योजना **प्रधानमंत्री ई–बस सेवा योजना** (18.08.2023) के अंतर्गत रायपुर शहर को 100 वातानुकुलित इलेक्ट्रिक सिटी बस प्रदाय कर संचालन किये जाने हेतु चयनित किया है, इसके लिए राज्य स्तर पर राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा को नोडल एजेंसी एवं रायपुर जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है। **100 इलेक्ट्रिक सिटी बसों के संचालन** हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड

अहमदाबाद का चयन ऑपरेटर के रूप में किया गया है, जिसमे ऑपरेटर द्वारा बसे उपलब्ध कराकर निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन किया जायेगा, साथ ही साथ बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन के संचालन संधारण भी ऑपरेटर के द्वारा किया जाना है। ऑपरेटर को स्वीकृति पत्र जारी किये जाने एवं अनुबंध किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत शासन के निर्देशानुरूप कार्यवाही किया जाना है।

सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में भी नगर निगम ने अपनी गतिविधियां शुरू की है। **प्रधानमंत्री 100 ई–बस सेवा** कार्य योजना हेतु जरवाय स्थित 2.02 हेक्टेयर आबंटित भूमि पर राशि रु. 14 करोड़ 33 लाख रु. की लागत से बस डिपो निर्माण एवं राशि रु. 12 करोड़ 27 लाख की लागत से इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की शुरूआत कर दी गई है।

57. शासन द्वारा बस डिपो सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु कुल 27 करोड़ 23 लाख रु. की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। **बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर** अन्तर्गत डिपो निर्माण हेतु जरवाय स्थित शासकीय भूमि 2.02 हेक्टेयर आबंटित की गई है। आबंटित भूमि पर रू. 11 करोड़ 17 लाख के लागत से बस डिपो निर्माण (बसों के चार्जिंग शेड, पार्किंग–बे, संचालन एवं संधारण केन्द्र, वॉशिंग–बे एवं कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन सहित अन्य आनुषंगिक कार्य) हेतु **कुल राशि रू. लगभग** 11-17 **करोड़** का कार्यादेश जारी किया गया है, जिसकी कार्य अवधि 1 वर्ष (वर्षाऋतु छोड़कर) है। वर्तमान में एजेंसी द्वारा कार्यस्थल पर समतलीकरण कार्य पूर्ण कर सरहदी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह **पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने** बस डिपो में विद्युतीकरण हेतु CSPDCL द्वारा कार्यादेश जारी कर कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी द्वारा सब स्टेशन निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 2 करोड़ 79 लाख का कार्यादेश 1 वर्ष की अवधि के साथ जारी किया गया है। बसों का संचालन

जन आवश्यकता अनुरूप हो यह ध्यान पर रख कर ही बस रूट तैयार किए जाएंगे। वर्तमान में शासन द्वारा 14 मार्ग अधिसूचित है। नवीन मार्गों के चयन हेतु RFP तैयार किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों, वार्डों में सर्वे करवाकर नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाकर नवीन मार्गों का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा।

58. हमारी परिषद् आम लोगों को शहर के एक स्थान से अन्यत्र जाने–आने के लिए सुगम, सुविधाजनक व पर्यावरण अनुकूल ई–सिटी बसों का संचालन शीघ्र शुरू करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं।

59. नगर निगम संपत्तियों के निर्धारण व भू–स्वामियो से इसके स्व निर्धारण हेतु डोर–टू–डोर सघन सर्वेक्षण के लिए एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

60. रायपुर नगर निगम की वर्तमान परिषद् ने राजस्व वसूली को पारदर्शी बनाने एवं हर व्यक्ति संपत्ति कर का स्वयं गणना कर भुगतान कर सकें, यह व्यवस्था तैयार की है। इसमें भवन भू–स्वामी ऑनलाइन माध्यम से **स्वनिर्धारण गणना पत्रक** भी अद्यतन कर सकते हैं।

61. बाजारों व व्यावसायिक परिसरों की रिक्त दुकानों से जहां एक ओर व्यवसायियों को उचित स्थल प्राप्त नहीं होता है, वहीं नगर निगम को राजस्व हानि उठानी पड़ती है। शहर के ऐसे कई बाजार है, जो वर्षो से रिक्त पड़े रहकर जर्जर होने की स्थिति में है। वर्तमान परिषद् ने इन परिसरों के रिक्त **दुकानों की आबंटन की प्रक्रिया में सुधार** हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

62. **प्रधानमंत्री आवास योजना** एक हितग्राही मूलक योजना है, जिसमें हितग्राही अंशदान लगाकर निर्माण कार्य प्रारंभ व पूर्ण किया जाता है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 1993 आवास स्वीकृत है, जिसमें से 830 नग आवास प्रगतिरत है एवं 30 नग आवास पूर्ण कर लिए गए है। आगामी 01 माह में 502 नग नये मकान पूर्ण कर आवासहीनों को स्वयं का आशियाना प्रदान करने का लक्ष्य नगर निगम ने तैयार किया है।

63. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ए.एच.पी. के तहत 1508 मकान में से 870 मकान पूर्ण किए गए है एवं शेष 638 मकान शीघ्र की पूर्ण कर लिये जाएगें। योजना अंतर्गत निर्मित सभी मकानों का आबंटन कर दिया गया है।

64. वित्तीय प्रबंधन हेतु म्युनिसिपल बांड जारी किए जाने का निर्णय लिया गया था। रायपुर नगर निगम 100 करोड़ मूल्य के नगर निगम बांड निर्गम की दिशा में अग्रसर है और वर्तमान में प्रारंभिक प्लेसमेंट मेमोरेंडम (पीपीएम) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के समक्ष दाखिल करने के चरण में है। इस बांड निर्गम का उद्देश्य निगम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार से मिलने वाले अग्रिम ब्याज प्रोत्साहन व राहत राशि के कारण बांड के माध्यम से वित्त की व्यवस्था अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक किफायती हो सकता है, इसके लिए परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अंतिम रूप से तैयार किया जा चुका है, जिसमें वित्तीय हब एवं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सिटी का प्रस्ताव शामिल है। यह परियोजना रायपुर को आधुनिक, व्यापारिक और तकनीकी केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। इस पहल से न केवल शहर की आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ आधार मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे और नगर निगम की

वित्तीय स्थिति को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु नगर निगम ने FMS (Fund Management System) लागू किया है। इस वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से राज्य, केन्द्र तथा स्थानीय निकाय की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों का आबंटन उपयोग एवं निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। यह प्रणाली नगर निगम की वित्तीय कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाती है।

65. नगर निगम अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण एवं समयमान, वेतनमान, पदोन्नति लाभ प्रदान करने संकल्पित है। विगत वित्तीय वर्ष में 125 आश्रित अभ्यर्थियों के लिए **अनुकंपा नियुक्ति** हेतु शासन से पद की मांग की गई थी, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत 35 पद में से 31 पद पर अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। केवल 04 रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। नगर निगम रायपुर अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला में कार्यरत 16 उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर **पदोन्नत** किया गया एवं निगम के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान, वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया।

66. रायपुर नगर निगम द्वारा नवीन पद संरचना हेतु शासन को प्रस्ताव भी प्रेषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा पदोन्नति, क्रमोन्नति, स्थायीकरण आदि हेतु निगम स्तर पर कमेटी तैयार कर अपर आयुक्त को इस कमेटी का प्रमुख बनाया गया है।

67. हमारी परिषद् ने **आंतरिक और बाह्य मार्गों में** पर्याप्त सड़क रोशनी व खेल मैदानों को सुविधाजनक बनाने पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की गई है। शहर के 09 खेल मैदानों में राशि रु. 5 करोड़ 89 लाख की लागत से 12 हाई मास्ट स्थापित किए जा रहे है।

68. भाठागांव शीतला चौक से महादेव घाट रायपुरा एवं एन.एच.–53 मार्ग से अग्रसेन धाम होते हुए वी.आई.पी. रोड तक राशि रु. 1 करोड़ 28 लाख की लागत से विद्युत पोल एवं एल.ई.डी. लाइट लगाए जा रहे है। इस हेतु 155 पोल स्थापित किए जा चुके है। शेष कार्य प्रगति पर है।

69. ऑफिस मोवा से ऐश्वर्या विंड मिल रोड तक एवं अटारी रोड तक राशि रु. 1 करोड़ 6 लाख की लागत से **विद्युत पोल एवं एल.ई.डी. लाइट** स्थापित किए जा रहे है, जिसमें अबतब 73 पोल स्थापित किए जा चुके है।

70. साइंट सेंटर के पीछे से रिंग रोड नंबर– 3 तक एवं मोवा मुख्य मार्ग से अशोका आईकॉन तक जाने वाली सड़क में राशि रु. 1 करोड़ 6 लाख की लागत से विद्युत पोल एवं एल.ई.डी. लाइट स्थापित करने की योजना प्रगति पर है, जिसमें 128 पोल अबतक स्थापित हो चुके है।

71. बाह्य क्षेत्र के लाइट विहीन खंभों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु राशि रु. 1 करोड़ 48 लाख की लागत से आवश्यक सभी प्रबंधों के साथ 2502 लाइट स्थापना का कार्य प्रगतिरत है।

72. अनाधिकृत अवैध निर्माण के विरूद्ध नगर पालिक निगम निरंतर एवं कठोर कार्यवाही कर रहा है, इसके लिए नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार नोटिस दिए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके लिए ई–पेनाल्टी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से अवैध अतिक्रमण अथवा सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने वालों को नोटिस दिया जाता है।

73. रायपुर नगर निगम द्वारा शहरी आवागमन को व्यवस्थित करने अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है, साथ ही सुचारू

आवागमन सुनिश्चित करने टीम प्रहरी द्वारा जिला प्रशासन, यातायात विभाग व पुलिस की मदद के साथ–साथ आम नागरिकों से भी सहयोग लिया जा रहा है।

विरोध के नाम पर जो बेवजह ज़हर उगलते हैं,
हकीकत में उनसे ही खूबसूरत शहर झुलसते हैं।

चूंकि पूर्ववर्ती परिषद् की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जनता को विश्वास में लेकर अतिक्रमण को रोकने गंभीर प्रयास किए जाते तो आज यह स्थिति निर्मित नहीं होती।

74. प्रमुख मार्गो पर अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम द्वारा सतत् रूप से कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

75. अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों की तरह ही सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाकर सड़क दुर्घटना के कारण बनने वालों पर भी नगर निगम ने सख्ती शुरू की है। ई–पेनाल्टी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निरंतर चालानी कार्यवाही की जा रही है। सभी सम्मानित पार्षद साथियों से भी अनुरोध है कि मार्ग बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों व स्थलों की पहचान करें, नगर निगम टीम को कार्यवाही के लिए सूचित करें और नागरिकों की सुविधाओं को निरंतर बढ़ाने में अपना सतत् योगदान जरूर देते रहें।

76. वर्षा ऋतु के पूर्व भू–जल संरक्षण की दिशा में नगर निगम ने गंभीरता से काम किया, इसका ही प्रतिफल है कि भारत सरकार द्वारा भू–जल संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रायपुर नगर निगम की सराहना करते हुए राशि रु. 50 लाख की विशेष स्वीकृति प्रदान की है। अब इस राशि से भू–जल संचयन व संरक्षण की दिशा में कार्यवाही को गति मिलेगी। इसके तहत निर्धारित प्रावधान अनुसार भवन स्वामियों से **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट** तैयार कराए जा रहे है, ऐसे भवन स्वामी जो

पिट निर्माण में रूचि नहीं ले रहे है, उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि को राजसात कर पंजीकृत हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के माध्यम से सभी जोनों में हार्वेस्टिंग पिट निर्माण के कार्य कराए जा रहे है।

77. नगर निगम क्षेत्र हेतु **ऑनलाइन होर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम** तैयार किया जा रहा है। पंजीकृत विज्ञापनकर्ता एवं विज्ञापन मीडिया की जानकारी अभी पोर्टल में दर्ज की जा रही है, जिसके उपरांत इस पोर्टल को लांच किया जाएगा।

78. रायपुर नगर निगम द्वारा **नवीन विज्ञापन पॉलिसी** तैयार कर 01 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है, इसके तहत विज्ञापन अनुमति को ऑनलाइन कर स्ट्रक्चर की सेफ्टी हेतु विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए है।

79. अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध **"ज़ीरो टोलरेंस"** नीति के तहत रायपुर नगर निगम ने ठोस व त्वरित कार्यवाही की है। अवैध प्लॉटिंग के 289 प्रकरण दर्ज किए गए एवं अवैध प्लॉटिंग स्थल में बने हुए मुरुम रोड को काटकर आवागमन एवं सूचना बोर्ड लगाया गया हैं। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग स्थल के भूखंड खसरा के संबंध में FIR दर्ज करने हेतु 253 पत्र संबंधित थानों को प्रेषित किए गए। इसके अलावा उप–पंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर को अवैध प्लॉटिंगकर्ता की जानकारी देने व रजिस्ट्री रोकने की कार्यवाही हेतु कहा गया है। नगर निगम के सभी जोन के अमले को निरंतर कार्यवाही के लिए कहा गया है। ऐसे अवैध प्लॉट के अधिग्रहण की योजना तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

80. राजीनामा हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के सरलीकरण हेतु शासन को पत्र भेजा गया है।

81. शहर विकास गतिविधियों में आम नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक संगठनों की भागीदारी ली जा रही है। इस कार्य में स्वच्छता दीदियों के अलावा स्व–सहायता समूहों की भी सहायता लेकर विकास गतिविधियों से हर आयुवर्ग को जोड़ने आगामी दिवसों में कार्यक्रमों का निर्धारण व क्रियान्वयन किया जाएगा।

82. रायपुर शहर अपने गौरवशाली इतिहास के साथ कई ऐतिहासिक स्थलों व घटनाओं का साक्षी है। रायपुर नगर निगम द्वारा शहर के सम्मानित वृद्धजनो को रायपुर ऐतिहासिक एवं पैराणिक महत्व के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया, इस तरह के आयोजन भविष्य मे भी होंगे।

रायपुर शहर के समग्र व संतुलित विकास की भावनाओं के साथ नगर पालिक निगम, रायपुर के वित्तीय वर्ष 2026–27 का लेखा–जोखा (बजट) सदन के पटल पर लाभ के बजट के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। इस वर्ष राजस्व वसूली का अनुमानित लक्ष्य 475 करोड़ 27 लाख 05 हजार रूपए निर्धारित किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मुख्य लेखा शीर्ष	बजट अनुमान 2026–27
01	प्रारंभिक शेष	207 करोड़ 65 लाख 90 हजार
02	कुल वार्षिक आय	1924 करोड़ 09 लाख 12 हजार
	योग	2131 करोड़ 75 लाख 02 हजार
03	कुल व्यय	2130 करोड़ 35 लाख 13 हजार
अंतिम शेष		**01 करोड़ 39 लाख 89 हजार का फायदा**

आय

रायपुर नगर निगम के आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आय का कुल अनुमान 1924 करोड़ 09 लाख 12 हजार रू. है, जिसमें पूंजीगत आय 962 करोड़ 15 लाख 55 हजार, डिपॉजिट वर्क आय 41 करोड़ 18 लाख 97 हजार रू. है।

अन्य राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार है :–

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियां	राशि
01	दर तथा कर	392 करोड़ 15 लाख 83 हजार
02	किराया पट्टों से आय	05 करोड़ 30 लाख
03	फीस एवं शुल्क	75 करोड़ 44 लाख 26 हजार
04	अन्य स्वच्छता प्रभार	47 करोड़ 56 लाख 70 हजार
05	विविध	43 करोड़ 66 लाख 68 हजार
06	अनुदान एवं अंशदान	356 करोड़ 21 लाख 13 हजार

व्यय

नगर निगम रायपुर के बजट वर्ष 2026–27 के प्रमुख व्यय अनुमान इस प्रकार है :–

मांग क्रमांक 01

वित्त लेखा एवं अंकेक्षण :– इस विभाग से संबंधित कुल व्यय 91 करोड़ 62 लाख 77 हजार का अनुमान है, जिसमें (6 एवं 7 वेतनमान) महंगाई भत्ता बकाया भुगतान एवं कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के भुगतान हेतु 5

करोड़ का व्यय एवं सामान्य भविष्य निधि बकाया भुगतान किये जाने हेतु 60 करोड़ 72 लाख का प्रावधान भी सम्मिलित है।

मांग क्रमांक 02

सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग :– उक्त विभाग हेतु कुल व्यय प्रस्ताव 57 करोड़ 69 लाख 99 हजार रू. का है। जिसमें स्थापना व्यय शामिल है।

मांग क्रमांक 03

नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग :– इस विभाग से संबंधित व्यय का कुल प्रस्ताव 15 करोड़ 93 लाख 91 हजार रू. है, जिसमें भू–अर्जन/भूमि का क्षतिपूरक मुआवजा 2 करोड़ रू. 20 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

मांग क्रमांक 04

लोक कर्म विभाग :– लोक कर्म विभाग से संबंधित कार्यों के लिए कुल प्रस्ताव 562 करोड़ 10 लाख 70 हजार रू. का प्रावधान है, इसके अंतर्गत प्रावधानित मुख्य विकास कार्य निम्नलिखित है :–

1. बड़े नालों का निर्माण	–	02 करोड़
2. सीमेंट मार्ग निर्माण	–	01 करोड़ 50 लाख
3. लाईब्रेरी भवन	–	05 करोड़ 80 लाख
4. वर्किंग वुमेन हॉस्टल हेतु	–	48 करोड़
5. फुटपाथ एवं पेवर निर्माण	–	50 लाख
6. चौराहों का सौंदर्यीकरण	–	01 करोड़
7. नाली निर्माण	–	02 करोड़

8. डब्लू.बी.एम. मार्ग – 20 लाख
9. महापौर निधि – 02 करोड़ 25 लाख
10. अत्यावश्यक कार्यो हेतु – 80 लाख
व अन्य कार्यो को शामिल किया गया है।

मांग क्रमांक 05

जल कार्य विभाग :– इससे संबंधित व्यय का अनुमान 104 करोड़ 88 लाख 52 हजार रू. का है, जिसमें पेयजल परिवहन कार्य हेतु 02 करोड़ 10 लाख एवं पॉवर पंप क्रय/ स्थापना कार्य हेतु 30 लाख, विद्युत व्यय हेतु 60 करोड एवं जल व्यवस्था हेतु 01 करोड़ का प्रावधान है।

मांग क्रमांक 06

राजस्व विभाग :– राजस्व विभाग हेतु 15 करोड़ 30 लाख 21 हजार व्यय का प्रस्ताव है।

मांग क्रमांक 07

खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस विभाग हेतु 76 करोड़ 97 लाख 81 हजार का प्रावधान रखा गया है, प्रमुख व्यय मच्छर उन्मुलन, आवारा कुत्तों के बधियाकरण, सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट, मशीन क्रय, सफाई मित्र योजना, चिकित्सालयों हेतु दवाई एवं उपकरण पर, व्यय किये जाने हेतु प्रावधानित किया गया है।

मांग क्रमांक 08

विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग :– इस विभाग हेतु 89 करोड़ 99 लाख 91 हजार रू. व्यय का अनुमान है, इसमें मुख्य रूप से मार्ग विद्युतीकरण हेतु 01 करोड़, सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यों हेतु 50 लाख, विद्युत सामग्री क्रय हेतु 02 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया है।

मांग क्रमांक 09

गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग :– इस विभाग हेतु 87 लाख 44 हजार व्यय का प्रावधान है।

मांग क्रमांक 10

महिला एवं बाल विकास विभाग :– इस विभाग हेतु 57 लाख 41 हजार का व्यय प्रस्ताव है, इसमे प्रमुख रूप से निगम क्षेत्र की निर्धन महिलाओं के लिए कुटीर उद्योगों के माध्यम से उन्हें स्व–रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

मांग क्रमांक 11

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग :– इस विभाग हेतु 8 करोड़ 19 लाख 29 हजार का प्रावधान है, साथ ही अनुसूचित जाति तथा जनजाति वार्डों के विकास कार्यो हेतु 6 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। इस वर्ग के युवाओं एवं महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का विशेष प्रावधान रखा गया है।

मांग क्रमांक 12

खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग :– खिलाड़ी के लिये खेल शिविर/खेल प्रशिक्षण/वार्षिक समारोह हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मांग क्रमांक 13

पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग :– इस विभाग के अंतर्गत नवीन उद्यानों की स्थापना की जाएगी साथ ही उद्यानों का संधारण, ओपन जिम स्थापना एवं हरित विकास के अंतर्गत वृक्षारोपण किए जाएंगे।

मांग क्रमांक 14

संस्कृति एवं पर्यटन मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग :– इस विभाग हेतु 3 करोड़ 94 लाख 51 हजार रू. व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु संगोष्ठियों के आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु, निगम कर्मचारियों एवं जनता के लिए संगीत क्लब एवं सांस्कृतिक क्लब के लिए विभिन्न प्रावधान किया गया है।

मांग क्रमांक 15

जोन व्यय :– जोन कार्यालयों के माध्यम से कुल 194 करोड़ 97 लाख 79 हजार व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रमुख व्यय प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

1. सफाई ठेका – 60 करोड़ 79 लाख 49 हजार
2. गलियों का कांक्रीटीकरण – 18 करोड़ 39 लाख 85 हजार
3. मार्ग संधारण – 11 करोड़ 48 लाख 05 हजार

4. सामुदायिक भवन – 09 करोड़ 36 लाख 80 हजार
5. समस्त भवनो का वार्षिक संधारण – 03 करोड़ 68 लाख 98 हजार
6. नालियों का वार्षिक संधारण – 07 करोड़ 55 लाख 11 हजार
7. पार्षद निधि – 05 करोड़ 30 लाख 40 हजार
8. सार्वजनिक कुओं और तालाबों की सफाई – 02 करोड़ 15 लाख 42 हजार

व अन्य कार्यो को शामिल किया गया है।

<u>मांग क्रमांक 16</u>

पूंजीगत व्यय के अंतर्गत कुल 834 करोड़ 46 लाख व्यय का अनुमान है, जिसमें प्रमुख है :–

1. सबके लिये आवास योजना – 45 करोड़
2. अमृत मिशन योजना – 15 करोड़
3. खारून नदी में मिलने से पूर्व नालियों के पानी का शुद्धीकरण हेतु ट्रीटमेंट प्लांट – 05 करोड़
4. अधोसंरचना मद – 60 करोड़
5. नगर विकास योजना/मार्ग चौड़ीकरण – 120 करोड़
6. बी.एस.यू.पी. – 01 करोड़
7. आश्रय शुल्क – 20 लाख़
8. वार्षिक संधारण – 15 करोड़ 50 लाख
9. पुष्पवाटिका योजना – 80 लाख
10. गोकुल नगर का विकास कार्य – 80 लाख
11. जिमखाना/व्यायाम शाला – 02 करोड़
12. उन्मुक्त खेल मैदान योजना – 80 लाख
13. पार्षदों की अनुशंसा के कार्य – 04 करोड 80 लाख
14. मुक्तिधाम योजना – 80 लाख

15. सार्वजनिक प्रसाधन योजना – 80 लाख
16. चौक चौराहो पर जेब्रा क्रॉसिंग का – 01 करोड़
17. पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत – 05 करोड़
18. वार्डों में आगंतुकों के लिये पथ प्रदर्शक पट्टिका एवं महत्वपूर्ण स्थलों के सूचक – 01 करोड़

19. धातु फ्रेम में महापुरूषों के जीवनी लेख– 20 लाख
20. प्रत्येक जोन में ई–गवर्नेस की स्थापना – 02 करोड़

व अन्य कार्यो को शामिल किया गया है।

मांग क्रमांक 17

डिपॉजिट वर्क :– इस मद में 40 करोड़ 38 लाख 97 हजार रू. का प्रावधान रखा है, इसमें प्रमुख रूप से जिला योजना मंडल के कार्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आदि के व्यय प्रावधानित हैं।

माननीय सभापति जी,

मैंने अपने अभिभाषण के हर बिन्दु के क्रियान्वयन को हमनें प्रमुखता दी है। मैं, अपने सभी जनप्रतिनिधियों और निगम प्रशासन की आभारी हूँ, जो विकास गतिविधियों को पूरा करने में अपना सहयोग व मार्गदर्शन मुझे निरंतर देते आ रहे हैं। पिछले बजट अभिभाषण पर मैंने बिन्दुवार शहर की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया है, जिसे मैंने विस्तार से आपके समक्ष पटल पर रखा है। हमारी इस परिषद ने शहर विकास व नागरिक अधिकारों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित किया है।

शहर की बुनियादी जरूरतों के साथ ही रायपुर के व्यवस्थित और समन्वित विकास के लिए हमारी परिषद ने कई निर्णय लिये है एवं जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के सहयोग से इस दिशा में हमने महत्वपूर्ण कार्य किये है, जिसके विषय में मैं अवगत कराना चाहूँगी :–

- रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता के साथ शहर की सुंदरता को बनाए रखने की दिशा में भी हमारी यह परिषद नागरिकों के विश्वास व प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। रायपुर को याद है पिछले 15 सालों तक शहर में राज करने वाली पूर्ववर्ती परिषद् की गतिविधियों का, जिसने शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये फूंकने में तो जल्दबाजी की, लेकिन शहर को फ्लैक्स मुक्त करने, किसी भी मार्ग को **नो फ्लेक्स ज़ोन** बनाने में रुचि नहीं दिखाई, उल्टे अपने आकाओं को खुश करने पूरे शहर की सड़कों, चौक–चौराहों को फ्लैक्स बैनरों से बदरंग करने में लगे रहे। हमारी परिषद ने मुख्य मार्गों व चौक–चौराहों को **नो फ्लेक्स ज़ोन** घोषित कर शहर की सुंदरता को बनाए रखने की प्रबल इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है। मैं शहर की जनता, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी, सामाजिक व सेवाभावी संगठनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे इस निर्णय में अपनी पूर्ण सहभागिता दी और साथ दे रहे हैं।

  साफ़–सफ़ाई और शहर की सुंदरता किसी एक निर्णय, एक प्रयास या एक दिन में संभव नहीं होती है। इसके लिए निरंतर व्यवहार परिवर्तन हेतु सभी को जागरूक करना आवश्यक होता है। किन्तु पूर्ववर्ती स्थानीय सरकार केवल डबल इंजन वाली सरकार होते हुए भी अपने और अपने नेताओं की ब्रांडिंग में ही मशगूल रही। वहीं वर्तमान परिषद ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी अपने शहर की सुंदरता को प्राथमिकता दे रही है और तमाम साधन–संसाधनों के बाद भी अपनी उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार के लिए बैनर पोस्टर से शहर को बदरंग करने की जगह अपने नागरिकों के दिलों में सीधे स्थान बनाया। जो राजनीतिक चश्मे से

नहीं बल्कि जनता की आँखों से उनके विश्वास और स्नेह से दिखाई दे रहा है।

- आवारा मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटनाओं और आवागमन में अव्यवस्था को लेकर परिषद् हर वर्ग से चर्चा कर ठोस रणनीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके लिए हम पशु पालकों को भी विश्वास में लेंगे और सभी मिलकर सर्वमान्य नीति निर्धारण सुनिश्चित करेंगे। पशु जन्म नियंत्रण नियम **2023** की अधिसूचना एवं विहित नियमों व निर्देशों के अनुक्रम में आवारा कुत्तों की आबादी को स्थिर या कम करने के लिए और मानव एवं कुत्तों के बीच संघर्ष कम करने हेतु नसबंदी एवं एन्टी रेबीज़ कुत्तों में टीकाकरण का कार्य नगर निगम द्वारा स्थापित **एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट** के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन 12 से 15 श्वानों का बधियाकरण, टीकाकरण एवं डीवार्मिंग किया जा रहा है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप आवारा श्वानों को खाना खिलाने हेतु वार्ड वार स्थान चिन्हांकित किया गया है एवं नोडेल अधिकारी नामित कर सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस स्टैंड एवं रेल्वे स्टेशन को चिन्हांकित कर इन परिसरों के प्रबंधन हेतु निर्देशित किया गया है जिससे की मानव एवं श्वानों के बीच संघर्ष को काम किया जा सके। ज़ोन क्रमांक 8 के अंतर्गत सोनडोंगरी में श्वानों के लिए पशु आश्रय स्थल का निर्माण पूरा कर दिया गया है, पिछले वित्तीय वर्ष में **5493** श्वानों का बधियाकरण, टीकाकरण और डीवार्मिंग किया गया है।

सभापति महोदय,

रायपुर के समग्र, समुचित व समन्वित विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के **संकल्प बजट में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना अंतर्गत रायपुर में सुविधाओं के उन्नयन व अधोसंरचना विकास हेतु**

राशि रु. 210 करोड़ 93 लाख का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह संकल्प बजट शहर के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, यातायात सुधारने, जल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए रायपुर के नागरिकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी, माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी को साधुवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय परिषद् के सामूहिक प्रयासों से रायपुर के सामाजिक, आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास को पर्याप्त गतिशीलता मिलेगी।

हम कोरे वादों से नहीं, काम से पहचान बनाएंगे,
घर–घर तक सेवा और सबका विश्वास ले जाएंगे।
जिम्मेदारी मिली है तो निभाएंगे पूरी,
शहर को आगे ले जाने का मिलकर इतिहास बनाएंगे।।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनसुविधाओं के विस्तार हेतु निम्नानुसार योजना का निर्धारण व बजट प्रावधान किए गए हैं –

1. **महिला शांति गृह :–** रायपुर नगर निगम द्वारा पहली बार मध्यम वर्ग की महिलाओं के मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य को पूरा करने राशि रु. 5 करोड़ की लागत से "महिला शांति गृह" की स्थापना की जाएगी। वर्तमान समय में घरेलू एवं सामाजिक दायित्वों के कारण महिलाओं पर अत्यधिक मानसिक दबाव रहता है, जिससे उन्हें विश्राम, आत्मचिंतन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

प्रस्तावित महिला शांति गृह एक सुरक्षित, शांत एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करेगा, जहाँ महिलाएँ अपनी दैनिक दिनचर्या से समय निकालकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगी। इस परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी :-

- एक सुव्यवस्थित **शार्ट टर्म डे शेल्टर** विश्राम कक्ष, जहाँ दिन में बैठने, आराम करने एवं सामूहिक गतिविधियों की सुविधा होगी।
- एक समर्पित परामर्श कक्ष, जहाँ प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा मार्गदर्शन एवं मानसिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- ध्यान एवं योग हेतु शांत ध्यान कक्ष, जो महिलाओं के मानसिक संतुलन एवं आंतरिक विकास को बढ़ावा देगा।
- स्वागत कक्ष, जहाँ आवश्यक जानकारी एवं समन्वय की व्यवस्था रहेगी।
- परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता एवं रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु परिसर में दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनसे प्राप्त आय का उपयोग भवन के संचालन एवं संधारण में किया जाएगा।
- इस परियोजना की विशेषता यह होगी कि इसका संचालन, प्रबंधन एवं समस्त गतिविधियाँ महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाएँगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी।
- इसके अतिरिक्त, इस केंद्र में समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर, योग एवं ध्यान कार्यशालाएँ, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम एवं महिला जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाएँगे, जिससे महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- महिला शांति गृह न केवल महिलाओं के लिए एक विश्राम स्थल होगा, बल्कि यह उन्हें मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास एवं

सामाजिक सहयोग प्रदान करने वाला एक सशक्त मंच भी सिद्ध होगा।

- महिला शांति गृह के माध्यम से विशेषकर घरेलू हिंसा से पीड़ित, निराश्रित/परित्यक्त, अस्थायी संकट की स्थिति में परेशान, विधवा, परित्यक्ता एवं जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर उन्हें मानसिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि समाज में महिला सुरक्षा और सम्मान की दिशा में भी एक मजबूत कदम होगा।

  महिला शांतिगृह स्थापना की यह पहल नगर निगम रायपुर की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। महिला शांति गृह शहर में एक संवेदनशील और प्रभावी सहायता केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

2. **रायपुर शहर में खारून महोत्सव का शुभारंभ :–** नगर निगम के बजट में इस बार खारून महोत्सव शामिल रहेगा। रायपुर के सांस्कृतिक एवं पर्यावरण पहचान के लिए प्रतिवर्ष खारून महोत्सव का आयोजन किया जावेगा। खारून नदी केवल एक जल स्त्रोत नही बल्कि रायपुर की जीवन रेखा व हमारी सभ्यता की साक्षी है। यह महोत्सव उसी आस्था व कृतज्ञता का पर्व रहेगा। इस आयोजन का उद्देश्य रायपुर वासियो को एक साथ जोड़ना और उनमें नदी जल संरक्षण व स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस आयोजन के माध्यम से हम अपनी जीवन रेखा खारून नदी का सम्मान करेंगे। रायपुर शहर की सांस्कृतिक विरासत को पहचान देने वाले वरिष्ठ नागरिको को सम्मान देने की योजना इस आयोजन में शामिल है।
3. मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के सम्मान मे निर्मित शहीद स्मारक भवन को वरिष्ठ नागरिकों की

सुविधा हेतु शहीद स्मारक परिसर में **लिफ्ट की सुविधा** उपलब्ध कराई जाएगी।

4. रायपुर शहर के भीड़–भाड़ वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को चिंहित कर वहॉ वाटर कूलर लगाये जाएंगे।
5. बूढ़ातालाब के समीप पुराना / धरना स्थल पर महिलाओ के लिए वेंडिग जोन बनाए जाएंगे।
6. रायपुर शहर की नियमित व व्यवस्थित साफ– सफाई के लिये हम प्रतिबद्ध है, इस हेतु राशि रु.1 करोड 50 लाख की लागत से रोबोटिक सक्शन मशीन क्रय किया जाएगा। इसी क्रम मे हमनें शासन के समक्ष राशि रु.1 करोड़ 50 लाख की लागत से ड्रेन मास्टर से खारून नदी एवं बड़े नालो की सफाई हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। सफाई हमारी प्राथमिकता है, पूर्व वर्षों के अनुभव को देखते हुए हमने सफाई को विशेष प्राथमिकता दी है और टाटा एस, मिनी टिप्पर, जेसीबी मशीन, पोकलेन, सक्शन मशीन, जटायू जैसी आधुनिक मशीने क्रय करने की योजना बनाई है।
7. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में **गौधाम योजना** आरंभ किए जाने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा गौधाम हेतु फुंडहर के समीप स्थल चिन्हित किया गया है। इसके प्रभावी संचालन के लिए नगर निगम कदम उठायेगा।
8. नगर निगम मे कार्य करने वाली कार्यरत महिलाओं के लिए रक्षा कवच के रूप में आत्म रक्षा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
9. प्रत्येक जोन के उपेक्षित 2 उद्यानों का चिन्हांकन कर उनका सौदर्यीकरण किया जायेगा।
10. बर्तन बैंक को महिलाओं को रोजगार से जोड़ने व सिंगल प्लास्टिक के उपयोग को रोकने तथा वार्ड स्तर पर कूड़े में कमी लाने के उद्देश्य रायपुर के प्रत्येक वार्ड में बर्तन बैक स्थापित किया जाएगा।

11. आमापारा स्थित कारी तालाब में पीपीपी मॉडल पर **पार्किंग सह वेंडिग जोन** बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।

12. गॉस मेमोरियल खेल मैदान के उन्नयन हेतु राशि रुपये 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस **खेल मैदान के पुनर्विकास** से स्थानीय युवाओं को खेल प्रशिक्षण एवं अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावना बढ़ेगी, साथ ही स्वास्थ्य, फिटनेस एवं सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

13. जे.एन. पांडेय उच्चतर माध्यमिक शाला तथा सप्रे **शाला एवं खेल परिसर विकास कार्य** हेतु राशि रुपये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन माध्यमिक शालाओं के विकास से शिक्षा और खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

14. शहर में विभिन्न स्थानों में आवश्यकता अनुसार **पे एंड यूज़ शौचालय** बनाए जाएंगें।

15. परंपरागत खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने रायपुर नगर निगम द्वारा व्यायाम शाला का जीर्णोद्धार किया जाएगा। रायपुर नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 व्यायाम शाला को चिहिंत कर उसका कायाकल्प किया जाएगा।

16. मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने रायपुर शहर की जनता की भावनाओं को पूरा मान देते हुए रायपुर शहर की जीवन रेखा खारून नदी के तट को उच्च स्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के सहयोग से लोक निर्माण विभाग ने लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत से **खारून रिवर फ्रंट** के निर्माण विकास और सौंदर्यीकरण की स्वीकृति प्रदान की है। खारून रिवर फ्रंट के पूरा हो जाने के उपरांत तट पर व्यवस्थित घाट से धार्मिक आयोजन और पूजा–पाठ सुगम होगा, वहीं पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय लोगों को लाभ होगा। व्यवस्थित तटबंधों के निर्माण से नदी जल को प्रदूषण

मुक्त रखने में सहायता मिलेगी, साथ ही मिट्टी का कटाव भी रूकेगा। महादेव घाट का जीर्णोद्धार वर्षों से प्रतीक्षित था। आस्था व रायपुर के इतिहास से जुड़े इस स्थल के कायाकल्प के निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति रायपुर के सभी नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ।

17. गत वित्तीय वर्ष के बजट पर मैंने 1000 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी की घोषणा की थी, किन्तु मुझे अपने शहर के युवाओं को यह बताने में भी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सर्व-सुविधायुक्त लाइब्रेरी में अध्ययन का लाभ मिले, युवा आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, इसके लिए हमने 1000 की जगह अब **1500 सीटर लाइब्रेरी** की सौगात अपने शहर को इस वित्तीय वर्ष में देने जा रहे हैं। इसके अलावा रायपुर शहर में युवाओं को अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य किसी महानगर की ओर पलायन न करना पड़े, इस दिशा में विचार-विमर्श कर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

18. माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी द्वारा रायपुर शहर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु बड़ी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। रायपुर नगर निगम द्वारा जोन क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में 274 विकास कार्यों हेतु अधोसंरचना मद से राशि रु. 233 करोड़ 69 लाख के विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी, सीसी रोड नालियों का निर्माण, पाइप लाइन विस्तार, सड़क मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे।

19. रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत नरैया और पंडरी बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन **दो वर्किंग वूमेन हॉस्टल** के पूरा होने से रायपुर आकर

अध्ययन या रोजगार से जुड़ी महिलाओं को आवास योग्य सुरक्षित स्थल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

20. मनुआस रियलिटी से महादेव घाट तक **सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य** (2.1 कि.मी) हेतु राशि रुपये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य से रायपुर से महादेव घाट रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा एवं महादेव घाट जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

21. केनाल रोड 2.0 (कलर्स माल के पीछे से प्रारंभ होकर 4.5 कि.मी. भाठागांव मार्ग तक) निर्माण हेतु राशि रुपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मार्ग एन.एच.–53 के समानांतर विकसित किया जाएगा एवं इस **मार्ग के निर्माण** हो जाने से भाठागांव, संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, साथ ही साथ शहरी विस्तार क्षेत्र के लिए यह मार्ग नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

22. कचना क्रॉसिंग से सेंट जेवियर होते हुए वी.आई.पी. रोड तक **सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य** हेतु राशि रुपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मार्ग कचना, अवंति विहार, खम्हारडीह को सीधे जी.ई. रोड एवं वीआईपी रोड से जोड़ेगा, जिसके कारण शहर के आंतरिक मार्गों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

23. शहर के **आवासीय अधोसंरचना में मूलभूत सुधार** करने एवं इसका सीधा लाभ शहर के नागरिकों को देने बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड के 1374 मकानों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

24. पंडरी कपड़ा मार्केट (दुल्हन साड़ी) से सीधी सड़क पंडरी मुख्य मार्ग तक **सड़क निर्माण कार्य** हेतु राशि रुपये 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस सड़क निर्माण से पंडरी कपड़ा मार्केट, सिटी सेंटर मॉल एवं नवीन निर्माणाधीन यूनिटी मॉल को बलौदाबाजार मार्ग से सीधे जोड़ा जा सकेगा, जिससे कपड़ा मार्केट क्षेत्र में यातायात के दबाव में कमी आएगी।

25. आमापारा चौक से हिंद स्पोर्टिंग मैदान तक **सड़क चौड़ीकरण कार्य** हेतु राशि रुपये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस सड़क चौड़ीकरण कार्य से आमापारा, सारथी चौक, लाखे नगर आदि क्षेत्रों में यातायात के दबाव में कमी आएगी एवं पीक आवर्स में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

26. टाटीबंध से आर.डी. तिवारी स्कूल तक **सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण** हेतु राशि रु. 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

27. एस.एम.सी. हॉस्पिटल से ऐश्वर्या विंडमिल होते हुए ब्रह्मकुमारी मुख्य मार्ग तक **सड़क चौड़ीकरण एवं पुलिया निर्माण** हेतु राशि रुपये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मार्ग निर्माण से शंकर नगर, मोवा, दलदल सिवनी, सड्डू एवं कचना क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही शंकर नगर से ब्रह्मकुमारी तक विधानसभा रोड के समानांतर एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

28. **अधोसंरचना विकास योजना** अंतर्गत महंत तालाब के पुनरोत्थान तथा रिंग रोड क्रमांक–5 के निर्माण हेतु भी पृथक रूप से राशि रुपये 1–1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

29. जिला प्रशासन, रोजगार एवं परामर्श केन्द्र व महाविद्यालयों के साथ समन्वय कर जॉब हेल्प डेस्क संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण, स्टार्ट–अप मार्गदर्शन शिविर, यूथ वालेंटियर प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसे उपयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास व रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

30. इस वित्तीय वर्ष में चौंक–चौराहों के सुधार व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राशि रू. 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

31. वर्तमान परिषद् प्रथम बजट के अनुरूप शहर में स्वचालित पार्किंग की सुविधा अपने नागरिकों को देने जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम मुख्यालय और पंडरी में **स्वचालित पार्किंग की सुविधा** शुरू हो जाएगी।

32. रायपुर के रायपुर के आंतरिक क्षेत्रों के साथ ही बाह्य क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को भी सुगमतापूर्वक स्वच्छ पेयजल मिले, इस विज़न के साथ वर्तमान परिषद अपने कार्यकाल के द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बढ़ते जनसंख्या घनत्व के साथ ही शहर से सटे बाहरी रिहायशी क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या ना हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति योजना को विस्तार दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत **इस वर्ष डुंडा में 130 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 150 एम.एल.डी. क्षमता के प्रस्तावित नवीन जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण** कार्य प्रारंभ होगा।इस संयंत्र के पूरा हो जाने से डुंडा क्षेत्र की बड़ी आबादी को शुद्ध पेयजल सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सकेगा।

33. **नगरोत्थान योजना के अंतर्गत खम्हारडीह में राशि रु. 23 करोड़ 38 लाख** की लागत से 25 लाख लीटर क्षमता की **नवीन पानी टंकी व पाइप लाइन** का निर्माण शुरू होगा। खम्हारडीह व ठक्कर बापा में जल

आवर्धन योजना के पूरा हो जाने से वार्ड क्रमांक– 09, 15, 16, 17, 18, 30, 31 एवं 32 के पचास हजार से भी अधिक रहवासियों को सीधा लाभ होगा एवं वर्षों से जल संकट से जूझ रहे परिवारों की पेयजल से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी।

34. सार्वजनिक जल आपूर्ति योजना का प्रभावी संचालन के लिए **जल बोर्ड** को प्रशासकीय व तकनीकी सक्षमता प्रदान की जाएगी।

35. **15वें वित्त आयोग** के अंतर्गत **लाभांडी व फुंडहर क्षेत्र में** राशि रु. 45 करोड़ 33 लाख की लागत से पेयजल योजना के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने के कार्य शुरू होंगे।

36. जल समस्या को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के द्वारा जोन स्तर पर **पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु** राशि 4 करोड़ 74 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से पेयजल विस्तार हेतु पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जावेगा।

37. रायपुर के तालाबों के संरक्षण व संवर्धन हेतु इस वित्तीय वर्ष में विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में महराजबंध तालाब, खो–खो व नरैया तालाब में एस.टी.पी. का संचालन शुरू किया जाएगा। एस.टी.पी. के संचालन शुरू हो जाने से दूषित जल को तालाब में प्रवाहित होने से पहले शोधित किया जाएगा। यह कार्य योजना पूर्ववर्ती सरकार व निगम परिषद् की अक्षमता की वजह से विगत 5 वर्षों से अपूर्ण रही, जिसे वर्तमान परिषद् अब अपनी निगरानी में पूर्ण करा रहा है। तालाब सफाई तथा रिजुविनेशन कार्य के लिए लगभग 1 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। इसमें हमारा प्रयास रहेगा राजा तालाब एवं शीतला तालाब चंगोराभाठा एवं अन्य तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा।

38. सड्डू में **पानी टंकी निर्माण** (4500 किलो लीटर क्षमता, 25 मीटर स्टेजिंग, राइजिंग लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं स्काडा सिस्टम सहित) कार्य हेतु राशि रुपये 38 करोड़ 93 लाख का प्रावधान किया गया है। इस टंकी निर्माण से रायपुर की पेयजल व्यवस्था तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी एवं आसपास के रहवासियों को पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

39. जल संचयन, जल संरक्षण व जल संवर्धन की दिशा में प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। वर्षा जल के संचयन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** की महत्ता व अनिवार्यता से शहरवासियों को अवगत कराया जाएगा।

40. विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत लगभग 70 लाख रुपए की लागत से मोवा से दलदल सिवनी तक एवं 39 लाख रुपए की लागत से रायपुर रेल्वे स्टेशन डिवाइडर की स्ट्रीट लाइट का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक व्यवस्था के तहत विभिन्न सड़कों पर विद्युत पोल व प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

41. रायपुर के विभिन्न स्थलों पर **भूमिगत विद्युतीकरण** हेतु राशि रुपये 245 करोड़ का प्रावधान संकल्प बजट में किया गया है–

- जी.ई. रोड – टाटीबंध चौक से आमापारा चौक तक – 40 करोड़
- जेल रोड – शास्त्री चौक से तेलीबांधा नाका चौक तक – 35 करोड़
- जलघर मार्ग – बिजली ऑफिस, कालीबाड़ी से भाठागांव चौक तक – 35 करोड़
- महादेव घाट रोड – लाखेनगर चौक से महादेव घाट तक – 65 करोड़
- आमापारा चौक से तेलीबांधा थाना चौक – 45 करोड़
- फाफाडीह चौक से वाल्टेयर ब्रिज तक – 25 करोड़

42. नगर निगम द्वारा राशि 2 करोड़ 85 लाख रू. की लागत से 500 किलो वॉट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस सोलर प्लांट की स्थापना से फिल्टर प्लांट के उच्चदाब देयक में कमी आएगी।
43. प्रदूषण संबंधी कारकों की निरंतर निगरानी की जाएगी एवं ई–व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ ही ई–चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चिन्हित कर इनका संचालन किया जाएगा।
44. महिलाओं व युवतियों को रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर फ्री स्किल ट्रेनिंग एवं स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मोवा में पिछले परिषद् की कार्यकाल में निर्मित **"लेडिज़ गारमेंट फैक्ट्री"** का संचालन इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा।
45. उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व–सहायता समूहों को **"अमृत मित्र" योजना** से जोड़कर इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम व स्वावलंबी बनाने नगर निगम द्वारा ठोस पहल की जाएगी।
46. रायपुर शहर में युवाओं को अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य किसी महानगर की ओर पलायन न करना पड़े, इस दिशा में विचार–विमर्श कर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा संचालित लाइब्रेरी एवं वाचनालयों की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।
47. शहर के बच्चों व युवाओं को खेलकूद की गतिविधियों से जोड़ने पूर्व में बनें ओपन जिम, बॉक्स स्पोर्ट्स स्थलों व खेल मैदानों की देखरेख की नियमित समीक्षा की जाएगी। इनके रख–रखाव हेतु जोन के साथ ही नगर निगम के खेल विभाग को पर्यवेक्षण क जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

48. रायपुर शहर में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने व खेल प्रतिभाओं को प्लेटफार्म प्रदान करने महापौर क्रिकेट लीग की तर्ज पर वार्ड व

शहर स्तर पर हर आयुवर्ग के लिए विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित होंगी।

49. बच्चों व युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से निर्मित 9 स्थानों पर बॉक्स क्रिकेट निर्मित है। इनके रख–रखाव व बेहतर संचालन के लिए जोन के साथ ही नगर निगम के खेल एवं युवा कल्याण विभाग को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

50. मच्छर से बचाव एवं एंटी लार्वा व दवाओं के नियमित छिड़काव किया जाता है। मच्छर उन्मूलन के लिए पूर्व से किये जा रहे प्रयासों के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं इसलिए स्थानीय पार्षदों से विचार–विमर्श कर ठोस रणनीति तैयार कर दवाओं के नियमित छिड़काव व मच्छर उन्मूलन गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

51. संवेदनशील व जल भराव संभावित क्षेत्रों की विशेष निगरानी होगी, यांत्रिक साधनों से अप्रैल माह तक प्रमुख नाला–नालियों की जल निकासी, मार्गों व संवेदनशील स्थलों की सफाई की जाएगी।

52. सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को देखते हुए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता महसूस होती है। नगर की कई स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों ने इस दिशा में रायपुर नगर निगम के साथ सराहनीय सहयोग देकर इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। चूंकि साफ–सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से दूरी व्यवहार परिवर्तन कारकों से जुड़ा विषय होता है, अतः बदलाव में समय लगता है। शहरी स्वच्छता व सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को नगर निगम एक जन अभियान के तौर पर संचालित करेगा एवं इसमें सभी आयुवर्ग को शामिल करने की रणनीति पर काम करेगा।

53. जल जनित एवं संक्रामक बीमारियों के रोकथाम व आपात स्थितियों से निपटने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के समन्वय में काम्बैट टीम गठित होगी।

54. सिटी सेनिटेशन वेस्ट के सुचारू, वैज्ञानिक और कुशल परिवहन हेतु राशि 13 करोड़ 50 लाख रू. की लागत से 300 टीपीडी क्षमता के **आधुनिक सेकेंडरी कलेक्शन व ट्रांसफर स्टेशन** का निर्माण किया जाएगा। इसके बन जाने से कचरे का संग्रहण, समेकन और परिवहन व्यवस्थित सुरक्षित और प्रभावी होगा।

55. ऑनलाइन डी–स्लज़िंग सेवाओं को सुचारू और पारदर्शी बनाने उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक आसानी से सैप्टिक टैंक की सफाई के लिए सेवाएं बुक कर ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। सेवा की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे तथा निर्धारित समय पर वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

56. सुरक्षित सुगम व जोखित मुक्त वातावरण में सफाई मित्र सैप्टिक टैंक की सफाई जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए आवश्यक उपकरणों का क्रय किये जाएंगे।

57. विभिन्न धार्मिक स्थलों से फूल एवं निर्माल्य एकत्रित करने रायपुर में निर्माल्य रथ का संचालन होगा। इनके माध्यम से पूजन उपरांत संग्रहित फूल व अन्य सामग्रियों का प्रसंस्करण तथा पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु 02 नग ई–वाहन क्रय किये जाएंगे।

58. रायपुर के घरों में डस्ट बीन मुहैया कराने की शुरूआत की गई है। चरणबद्ध रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरों से निकलने वाले सूखे व गीले कचरे पृथक कर कचरा संकलन वाहन में देने नगरवासी जागरूक बनें।

59. रायपुर शहर के वृद्धजनों को सुविधाएं देने के लिए नगर निगम संकल्पित है। इनके लिए पार्क एवं सार्वजनिक स्थलों पर बैठने के लिए विशेष बैंच लगाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य जांच के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प लगाए जाएंगे। इनके अलावा नगर निगम के कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिक की सहायता एवं उन्हें प्राथमिकता देने के लिए पृथक काउंटर/खिड़की की व्यवस्था की जाएगी।

60. रायपुर नगर निगम का **"माय सिटी ऐप"** संचालित है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग आम नागरिक करते है। संपत्ति कर, जल कर, भवन अनुज्ञा आदि सेवाओं व निगम से जुड़ी सुविधाओं की सहायता लेने नगरवासी वर्तमान में **"मोर रायपुर ऐप"** का उपयोग करते है। इसके अलावा चैट बॉट, निदान–1100 जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक जोन में एकीकृत सेवा केन्द्र के संचालन को इस वित्तीय वर्ष में और भी सशक्त बनाया जाएगा।

61. नगर निगम के बाजारों, परिसरों, दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया सुगम की जाएगी, जिससे कि इन रिक्त स्थलों का विक्रय कर राजस्व में वृद्धि की जा सकें, साथ ही व्यवसायी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकें।

62. 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत रायपुर के उद्यानों एवं शहर की हरियाली के संरक्षण हेतु 98 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मुख्य मार्गों व डिवाइडर में वृक्षारोपण, सिंचाई व्यवस्था, लैंड स्कैंपिंग, उद्यानों का संधारण व हरित विकास किया जाएगा।

63. नगर निगम द्वारा **रेंटल गार्डन योजना** शुरू की जाएगी, जिसके तहत शहर की नर्सरी, पौधा विक्रेता एवं गार्डनिंग से जुड़े उद्यमियों को नगर निगम के चयनित उद्यानों में निर्धारित स्थान किराया पर उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें उस उद्यान के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

64. वृद्धजनों के लिए विभिन्न उद्यानों में निर्मित बापू की कुटिया के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित किया जाएगा एवं उद्यान एवं बापू की कुटिया के समीप प्रसाधन कक्ष की सुविधा व बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी।

65. उद्यानों व सार्वजनिक स्थल पर स्थापित **ओपन जिम** का लाभ क्षेत्रवासियों को मिलता रहे, इस दिशा में नगर निगम के खेल विभाग को जोन अधिकारियों के साथ समन्वय व सतत् निगरानी के संबंध में दिशा–निर्देश दिए गए है।

66. तृतीय लिंग समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने व सम्मान पूर्वक जीवन में नगर निगम सहायक होगा एवं इनके लिए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।

67. रायपुर के युवाओं को उनके सृजनात्मकता व उन्नत कौशल से जुड़े योगदान के लिए युवाओं को "रायपुर युवा रत्न" सम्मान प्रदान किया जाएगा।

68. महापुरूषों, स्वतंत्रता सेनानियों व समाज सुधारकों के आदर्शों व राष्ट्रीय मूल्यों से जन सामान्य को अवगत कराने नगर निगम द्वारा विशेष अवसरों पर पुष्पांजलि व अन्य कार्यक्रम आयोजित होते है। इन आयोजनों के संबंध में निर्धारित शिष्टाचार नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में गरिमामय आयोजन हेतु निर्देशित किया गया है।

69. सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने व स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों व सांस्कृतिक समूहों को मंच प्रदान करने नगर निगम द्वारा समय–समय पर सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें हस्तशिल्प, लोककला, संगीत–नृत्य महोत्सव जैसी गतिविधियों का समावेश होगा।

70. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, अधिकारी–कर्मचारियों को पदोन्नति, समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा पर मिले, इस दिशा में कार्यवाही की जाएगी। नवीन पद संरचना हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे।

71. जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर वेंडिंग जोन तैयार किए जाएंगे। वेंडिंग जोन के निर्धारण में ध्यान रखा जाएगा कि आवागमन या लोकहित प्रभावित न हो और लघु व्यवसायी निश्चिंत होकर अपने व्यवसाय का संचालन कर सकें।

72. स्व–सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम से जोड़ने हेतु विशेष पहल की जाएगी।

73. रायपुर शहर के यातायात सुधार, शहरी आधारभूत ढांचा विस्तार, शैक्षणिक, स्वास्थ्य व नागरिक सुविधाओं व सेवाओं साथ ही महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए नगर निगम रायपुर प्रतिबद्ध है।

"जो कहा है, वो करके दिखाएंगे,
हर वादे को हकीकत में बदल जाएंगे।
ये बजट नहीं, दृढ विश्वास की नींव है,
हम सब मिलकर नया इतिहास बनाएंगे।

मा. अध्यक्ष महोदय,

एक साल का प्लान मैंने अपने बजट भाषण में रखा है। पिछले वर्ष जो प्लान एक वर्ष के लिए मैं और मेरी परिषद ने मिलकर तय किए थे, उसे पूरा करने के लिए हमनें ईमानदारी से प्रयास किए और अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए हमनें दिन रात एक किया है।

महोदय,

हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति के आगे सारी अड़चनें घुटने टेक देती हैं। वर्तमान बजट केवल आकड़ों का लेखा–जोखा नहीं है बल्कि राजधानी के हर नागरिक की आशाओं का प्रतिबिंब हैं। पिछले वर्ष की उपलब्धियां हमारी नींव है और आगामी वर्ष के लक्ष्य हमारी उड़ान। हम एक ऐसे रायपुर की परिकल्पना कर रहे हैं जहां आधुनिकता भी हो और अपनी माटी की सुगंध भी, जहां विकास की चमक भी हो और हरियाली भी।

मैं आज सदन के सभी सदस्यों से आह्वान करती हूँ कि आइए, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर शहर **हमर रायपुर** को देश के मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलें।

ना रुकेंगे हम ना थकेंगे हम, रायपुर की शान बढ़ाएंगे

हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, इसे सच करके दिखांएगे।

आइए, रायपुर शहर के सम्मानित नागरिकों ने जिस विश्वास और स्नेह के साथ नगर विकास की नीतियों के निर्माण व उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम सभी को सौंपी है, उसे ईश्वर प्रदत्त कार्य मानते हुए पूर्ण संकल्प एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

धन्यवाद...

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

मीनल चौबे
महापौर,
नगर पालिक निगम, रायपुर